जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

जालोर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

जालोर, शुक्रवार 4 अप्रैल, 2025

विचार बिन्दु

दुरात्मा के लिए देश भक्ति अंतिम शरण है। –जॉन्सन

क्या परिसीमन पर लगी रोक को सन् 2026 से 25 वर्ष और नहीं बढ़ाया जा सकता?

संविधान के अनुसार परिसीमन आबादी के आधार पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था है कि जनगणना के बाद सीटों का एडजस्टमेण्ट नये सिरे से होगा। परिसीमन (Delimitation) एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है जिसके अनुसार किसी देश या राज्य में चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया जाता है, ताकि जनसंख्या में बदलाव को ध्यान में रखते हुये चुनावी क्षेत्रों को न्याय संगत रूप से विभाजित किया जा सकते, फलस्वरूप सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो सके। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक का वोट समान मूल्य का हो। यह कार्य परिसीमन आयोग, जो एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 82 व अनुच्छेद 170 के अनुसार किया जाता है, इसकी सिफारिश बाध्यकारी है, इसके आदेशों में कोई दखल नहीं दे सकता। कोर्ट का भी दखल नहीं है। अनुच्छेद 81 व अनुच्छेद 82 को समझने के लिये हमें इनमें जो संशोधन हुये हैं, उन्हें गइराई से समझना होगा विशेषकर संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 आदि।

चुनावी प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनने के लिये परिसीमन जरूरी है। प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के बदलाव के कारण, सभी को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। हर वर्ग के नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिलना चाहिये। परिसीमन के समय अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर सीटों का निर्धारण होना चाहिये।

यह निर्विवाद कथन है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटें पुनः नये सिरे से तय होती है। एक विचार धारा के अनुसार सत्तर के दशक में एमरजेन्सी के समय उस समय की कांग्रेस सरकार ने परिसीमन के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों का आवंटन रोक दिया था ताकि परिवार नियोजन की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के विषय पर कोई नुकसान नहीं हो। उस समय यानी 2001 में वाजपेयी सरकार थी। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमायें नये सिरे से निश्चित की गई; किन्तु दक्षिण में विरोध के कारण सीटों में बदलाव नहीं हो सका। उत्तर व दक्षिण के राज्यों में टकराव न हो, इसे रोकने के लिये 2002 में संविधान संशोधन के माध्यम से सीटों का परिसीमन 2026 तक रोक दिया गया। इन संशोधनों से यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद ही परिसीमन प्रक्रिया होगी। इतने समय बाद अब प्रक्रिया प्रारम्भ की जाना प्रस्तावित है। इतने समय में आबादी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य असंतुलन बढ़ा है, यही आज उत्तर व दक्षिण के राज्यों में टकराव का कारण है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उत्तर के राज्यों के मुकाबले में उनकी सीटों परिसीमन से कम हो जायेंगी। उनका कहना है कि आबादी नियंत्रण की योजना में सहयोग देने के कारण उन्हें यह सजा दी जा रही है जो उचित नहीं है।

दक्षिण के लगभग सभी राज्य डीएमके की लीडरशिप में साथ खड़े हैं और परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वहीं उत्तर के हिन्दी बोलने वाले राज्य बंटे हुये हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तामिलनाडू को सहयोग दे रहे हैं और आरजेडी परिसीमन की प्रस्तावित प्रक्रिया का समर्थन कर रही है। तामिलनाडू के सीएम एम के स्टालिन की अध्यक्षता में एक संयुक्त कार्यवाही समिति का गठन हुआ है, उसने परिसीमन में पारदर्शिता की मांग की है। समिति ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है कि अगले 25 साल तक लोकसभा की संख्या जो 543 है उसे यथावत रखा जावे।

यहाँ यह कहना उचित होगा कि अब तक 4 परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1972 व 2002 में बने हैं। उपरोक्त कथन के अनुसार यह स्पष्ट है कि 2026 तक सीटों की संख्या फ्रीज करने का प्रावधान संवैधानिक है। इससे यह भी निश्चित हो चुका है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर सीटों का नये सिरे से समायोजन/समन्वय/सुधार/सामंजस्य (Adjustment) होगा। उपरोक्त लिखे गये तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 82 भी यही संदेश देता है कि जनगणना के बाद ही एडजस्टमेन्ट होगा। साथ ही यह भी सिद्धान्त स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 81 के तहत् एक नागरिक एक वोट और एक कीमत का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

जैसा ऊपर लिखा है कि परिसीमन आबादी के साथ जुडा हुआ है। 1971 में जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 543 थी उस समय आबादी 55 करोड़ थी। अब आबादी 145 करोड़ हो चुकी है अतः ये सीटें 850 तक हो सकती हैं। सम्भवतः यही कारण है कि लोकसभा की नई बिल्डिंग में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। आबादी बढ़ने से एक एमपी पर 20 से 28 लाख तक की आबादी का भार है। कुछ नेता तो यहां तक कहते हैं कि हमारे एमपी ऑवर टाइम काम करते हैं। टीवी पर हम लोकसभा की कार्यवाही देखते हैं उससे तो यह प्रतीत होता है कि हमारे माननीय सांसदों पर श्रम कानून लागू होना चाहिये जहां यह माना गया है कि "काम नहीं तो दाम नहीं (No Work No Wages)"।

> **क्या परिसीमन पर लगी रोक को 25 वर्ष और नहीं बढ़ाया जा सकता। नेताओं के संग वार्ता व चर्चा कर समस्या का सर्वमान्य हल तलाशना ही देश हित में होगा। भारत विकास के मार्ग पर है, उसकी गति नहीं रूकनी चाहिये। हमें भारत को विकसित देश बनाना है। जहाँ देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय समता, समानता व समरसता से प्राप्त हों।**

परिसीमन की समस्या वास्तविक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिसीमन के कारण उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण के राज्यों की सीटें कम होंगी। परिसीमन का यह विवाद कहीं क्रूर रूप धारण न करले। इस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है। नई जनगणना की कार्यवाही प्रारम्भ होनी चाहिये ताकि परिसीमन की कार्यवाही शीघ्र हो सके। यह विवाद बहुत समय से रूका हुआ है, इसे विस्फोटक होने से रोकना होगा। इसका हल खोजना होगा। परिसीमन विवाद का हल तो ढूँढना ही होगा। विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिये हैं। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की रणनीति पर चलते हुये, एक नया नारा दिया है, 'जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक'।

केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण के राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिये उन्हें दण्डित नहीं किया जावेगा। उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। देश के गृहमंत्री अमित शाह भी सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रोरेटा के अनुसार राज्यों में सीटों का वितरण होगा। किसी भी राज्य में सीटें कम नहीं होंगी।

परिसीमन की समस्या को निपटने के कई विकल्प सुझाये जा रहे हैं। संसद 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित कर चुकी है। इसके योजना के साथ लागू किया जावे। जनगणना हो और उससे प्राप्त आंकडों के आधार पर बाद में विशेषज्ञों से सलाह लेकर परिसीमन किया जावे। 33% सीटें बढ़ाई जावें। महिला आरक्षण से बढ़ने के बाद संसद की सीटें 543 से 722 होगी। इन्हें गणना की सरलता के लिये 725 किया जावे। ये सीटें 15 वर्ष के लिये बढ़ाई जावे। संसद चाहे तो 15 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह ध्यान रहे कि एससी व एसटी के आरक्षण की 33% सीटें इस वर्ग की महिलाओं के लिये निश्चित की जावे।

एक अन्य प्रक्रिया में वोटर संख्या से सीट बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्टालिन के प्रस्ताव पर भी विचार किया जावे। इसके अनुसार लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या 543 से सीमित किया जावे और आगे आने वाले 25 वर्षों तक सीटें न बदलें। इस संबंध में केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया जा सकता है, जिस पर सदन में चर्चा हो। कुछ विशेषज्ञों ने और भी सुझाव दिये हैं। इन सब पर चर्चा होनी चाहिये। सभी सुझावों का अधार होगा कि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम न हों। ऐसा कोई कदम न बढ़ाया जावे जिससे ट्राबल सीटों में कमी हो। कानून के अनुसार परिसीमन जनगणना के बाद, परिसीमन अधिनियम संसद पारित करे। आयोग का गठन करे जो भारत निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग करते हुये कार्य करे। प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानसभा हो। 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पाण्डीचेरी में यह व्यवस्था है।

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि परिसीमन का विवाद देश के लिये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यह कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि बीजेपी उत्तर में अच्छी स्थिति में है अतः वह परिसीमन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी करना चाहती है। बीजेपी से जो पार्टियां विरोध में है वे एक साथ खडी होकर उत्तर दक्षिण की लडाई को हवा देना चाहती है। चेन्नई में हुई जोइन्ट एक्शन कमेटी की मीटिंग में यह स्पष्ट दिखाई दिया कि विपक्ष के साथ दक्षिण की पार्टियों के अतिरिक्त पंजाब व उडीसा के राजनेता भी साथ दे रहे हैं। इण्डिया के सभी घटक दलों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। इस प्रकार उत्तर दक्षिण का विवाद पुनः जिन्दा हो उठा है। जोइन्ट एक्शन कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है कि परिसीमन पर लगी रोक, जिसका उल्लेख ऊपर किया है, इसे 25 वर्ष और बढ़ाकर 2050 तक कर दिया जावे। अन्यथा उत्तर का वर्चस्व हो जावेगा। अनुच्छेद 82 के अनुसार मियाद 2026 में समाप्त हो रही है। तेलंगाना के नेता यह कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन सम्भव है किन्तु लोकसभा की सीटें न बढ़ाई जावें। उनका विश्वास है कि अनुसूचित व जनजाति के आरक्षित सीटें बढ़ाई जावें और 33% महिला आरक्षण देने से समस्या का समाधान हो सकता है। लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 है इनमें 24% सीटें अर्थात् 130 सीटें दक्षिण राज्यों की हैं, इसे 33% बढाया जावे। गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि दक्षिण राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। वित्तमंत्री का कहना है कि परिसीमन केवल जनसंख्या आधारित नहीं है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीति की पालना की है अतः उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता। असमंजस्य की स्थिति है, पिक्चर स्पष्ट नहीं है। विवाद है, इसका समाधान तो ढूंढना ही होगा। देश विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है, इसकी गति नहीं रूकनी चाहिये।

प्रश्न है क्या परिसीमन पर लगी रोक को 25 वर्ष और नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे 2050 तक विवाद पर रोक लग जावेगी। संविधान के अनुच्छेद 82 में जो संशोधन 2026 के पश्चात् की गई जनगणना के आंकडे प्रकाशित नहीं होने तक के बाबत है, वैसा ही प्रावधान संविधान संशोधन किया जावे। नेताओं के संग वार्ता व चर्चा कर समस्या का सर्वमान्य हल तलाशना ही देश हित में होगा। भारत विकास के मार्ग पर है, उसकी गति नहीं रूकनी चाहिये। हमें भारत को विकसित देश बनाना है। जहाँ देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय समता, समानता व समरसता से प्राप्त हों।

भारत, तेरी जय हो, जय हो, जय हो!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

परिसीमनः लोकतंत्र की नई रूपरेखा और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में कदम

राजेन्द्र राठौड़

दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी कहती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिले और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में संतुलित मतदाता संख्या हो। इन दिनों देशभर में लोकसभा / विधानसभाओं के परिसीमन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं व बहस जारी है।

संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित उचित प्रतिनिधित्व के प्रावधान के अनुसार लोकसभा के सांसद को 5 लाख से साढे 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये परन्तु 1976 से अब तक परिसीमन पर 84वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 2026 तक लोकसभा / विधानसभा के परिसीमन व पुनर्निर्धारण पर लगी रोक के कारण वर्तमान में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हो गई।

समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और सामाजिक संरचना में बदलाव के कारण परिसीमन की जरूरत इसलिए भीबढ़ जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मतदाता की आवाज समान रूप से सुनी जा सके।इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निर्धारित समयावधि के बाद संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससेलोकसभा और विधानसभाओं के क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित और मतदाताओं की संख्या पुनर्निर्धारित की जाती हैं। वर्तमान में जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण जनप्रतिनिधि निर्धारित संख्या से कहीं ज्यादा आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार जब पूर्व में लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया था तब देश की आबादी 55 करोड़ थी जो आज 145 करोड़ से ज्यादा है।मौजूदा जनसंख्या के अनुसार अब एक सांसद 30 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाई जाना समय कीस्वाभाविक संवैधानिक मांग है।

यह भी सही है कि पिछले पाँच दशकों में देश में जनसंख्या में वृद्धि असामान्य तौर से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। अब परिसीमन को लेकर तमिलनाडु व कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्य इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि उनको भय सता रहा है कि यदि लोकसभा सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 81 के आधार पर निर्धारित की गई तो उन्हें नुकसान होगा क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया है। इन राज्यों का यह मानना है कि परिसीमन होना उनके द्वाराकिये गये अच्छे कार्यों के लिए दंड देने के समान ही है। इसी कारण से दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दल आगामी 25 तक लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के लोगों को आश्वस्त किया है कि दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा की एक सीट भी कम नहीं होगी। अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो दक्षिण भारत के राज्यों को उचित हिस्सा मिलेगा। वर्तमान में दक्षिण के पांच राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के राज्यो में लोकसभा के 543 सदस्यों में से 130 सदस्य चुनकर आते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 82का यह प्रावधान है कि देश में प्रत्येक जनगणना के बाद संसद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। यह आयोग दो प्रमुख कार्य करेगा। पहला –लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा ताकि जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करेगा जिससे इन वर्गों को संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं संविधान का अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभाओं की सीटों के निर्धारण से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सीटें तक हो सकती हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार हर 10 वर्ष पर जनगणना होगी और उसके आंकड़ों के आधार पर हर 10 वर्ष में परिसीमन होगा और लोकसभा / विधानसभाओं में आवश्यकता होने पर सीटों में बढ़ोतरी होगी। संविधान में प्रावधान किया गया है कि हर परिसीमन के लिए जनगणना के बाद नए आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

भारत में परिसीमन की यह परंपरा 1951 की पहली जनगणना से शुरू हुईजब संविधान के तहत पहली बार परिसीमन आयोग गठित किया गया था। अब तक भारत में चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है– 1952, 1963, 1973 और 2002 में। इस आयोग को संविधान द्वारा विशेष शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान की गई हैं जिससे इसके निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

1952 में भारत में कुल 489 लोकसभा सीटें थीं, जो 1973 में बढ़कर 543 हो गईं। हालांकि 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के तहत परिसीमन पर 25 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी।

इसके बाद 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 25 वर्षों के लिए परिसीमन को और टाल दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2001 के संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या अब 2026 के बाद ही बढ़ाई जा सकती है।

अंतिम परिसीमन के बाद से लेकर अब तक जनसंख्या में बड़ा बदलाव आया है, जिससे कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अत्यधिक हो गई है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मतदाता हैं। इससे एक असंतुलन पैदा हो गया हैजो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

आज देश में सांसदों पर जनप्रतिनिधित्व का असंतुलन एक गंभीर चुनौती बन चुका है। लक्षद्वीप में एक सांसद मात्र 48,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक सांसद 20-30 लाख लोगों की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों की आवाज उतनी प्रभावी ढंग से संसद में नहीं पहुंच पाती। इसलिए परिसीमन वर्तमान की आवश्यकता है। भारत में प्रति सांसद औसत जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का एक सदस्य लगभग 7.4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटेन में यह संख्या मात्र 1.2 लाख है।

लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। इसका उद्देश्य भी यही है कि हर वर्ग के नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिले। चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों की बात कई बार की जाती है। इसलिए जब भी परिसीमन किया जाता है, तब अनुसूचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए आरक्षित सीटों का भी निर्धारण संवैधानिक प्रावधानो के अनुसार होता है।

एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत के तहत, हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। परिसीमन का उद्देश्य प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना हैजिसमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह अकेला निर्धारक नहीं हो सकता। जैसे एससी-एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें पहचान-आधारित प्रतिनिधित्व दर्शाती हैं, वैसे ही राज्यों का प्रतिनिधित्व भी केवल जनसंख्या पर निर्भर नहीं रह सकता। लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए यदि 33 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाती हैं तो कुल सीटों की संख्या 725 हो जाएगी। यह न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त करेगा बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना को भी अधिक समावेशी बनाएगा। केंद्र सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी राज्यों को समान अवसर मिले और देश की संघीय संरचना मजबूत हो। साथ ही दक्षिण राज्यों की सभी आशंकाओं को भी दूर कर रही है।

परिसीमन केवल राजनीतिक संतुलन का मुद्दा नहीं बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा–"एक नागरिक–एक वोट–एक मूल्य"–के सिद्धांत को सुनिश्चित करने का एक जरिया भी है। यदि इसे निष्पक्षता और समावेशी दृष्टिकोण से लागू किया जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत प्रभावी और प्रगतिशील बना सकता है।

–राजेन्द्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

सांवलिया जी सेठ के भंडार से 4.87 करोड़ रुपए की आमद

गत 28 मार्च को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती दो चरणों में संपन्न

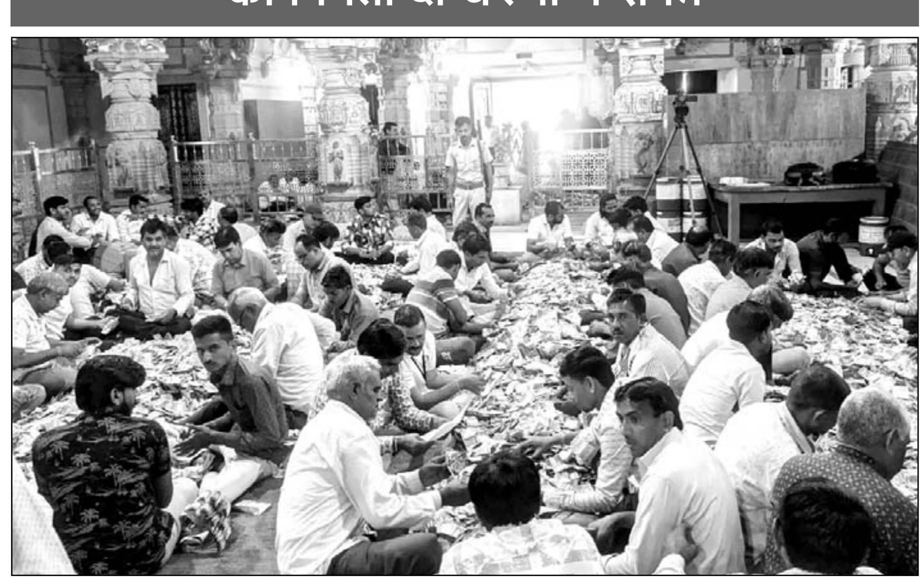

भंडार से निकली राशि की मंदिर कर्मचारियों ने गिनती की।

मंडफिया, (निसं)। भगवान श्री सांवलियाजी के दरबार में गत 28 मार्च को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती दो चरणों में संपन्न हुई

मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर ने बताया बुधवार शाम को संपन्न हुई दूसरे चरण की गिनती से 7 लाख 2 हजार 895 रूपए की नगद प्राप्ति हुई। इससे पूर्व प्रथम चरण में हुई भंडार गिनती से 4 करोड़ 80 लाख 27 हजार 911 रूपए नगद प्राप्त हुई थे। प्रशासनिक अधिकारी टेलर ने बताया कि दोनों चरणों की गिनती को मिलाकर भंडार से 4 करोड़ 87 लाख 30 हजार 806 रुपए नगद प्राप्त हुए। टेलर ने बताया कि भंडार से निकले सोने-चांदी एवं मंदिर कार्यालय में जमा सोने चांदी का तोल भी किया गया, जिसमें भंडार से 60 ग्राम सोना व 18 किलो 900 ग्राम चांदी प्राप्त हुई एवं मंदिर कार्यालय से 33 ग्राम 900 मिलीग्राम सोना एवं 28 किलो 685 ग्राम चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। भंडार गिनती में भादसोड़ा नायब तहसीलदार शिवशंकर पारीक, प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, मंदिर प्रभारी राजेंद्र कुमार शर्मा, संपदा प्रभारी भेरुगिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह राजपूत, लेहरी लाल गाडरी, कालूलाल तेली, बिहारीलाल गुर्जर, जितेन्द्र त्रिपाठी सहित मंदिर एवं बैंक कर्मचारी उपस्थित थे।

स्कूटी नहीं मिलने पर छात्राओं का प्रदर्शन

डूंगरपुर, (निसं)। जिले में काली बाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 की एक हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी का आज भी इंतजार है। स्कूटी नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर 15 दिन में स्कूटी वितरण की मांग की है। वहीं 15 दिन में स्कूटी नहीं मिलने पर उग्र आन्दोलन की चेतावनी दी है।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 में चयनित मेधावी छात्राएं गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान स्कूटी नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्राओं ने बताया कि कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 में एक हजार 168 छात्राओं का चयन हुआ था, जिसमें से 168 छात्राओं को तो स्कूटी का वितरण किया जा चुका है। वहीं शेष एक हजार छात्राओं को आज तक स्कूटी का वितरण नहीं हुआ है, जबकि सत्र 2023-24 की छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। छात्राओं ने बताया कि वर्ष 2024 में उनके नाम से स्कूटी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। स्कूटियां टीवीएस कम्पनी के डीलर के गोदाम में पड़े-पड़े खराब हो रही हैं, लेकिन सरकार ने उन स्कूटियों का अभी तक भी वितरण नहीं किया है। मेधावी छात्राओं ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देकर 15 दिन के अंदर स्कूटी का वितरण करने की मांग की है।

मंदिर और पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा

डूंगरपुर, (निसं)। ग्राम पंचायत माडा के लोगों ने गुरुवार को कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने मंदिर, सार्वजनिक जमीन और पार्क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नारेबाजी की। प्रशासन से अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की गुहार लगाई।

ग्राम पंचायत माडा के सरपंच, उप सरपंच रमेश लबाना, पंचायत समिति सदस्य, वार्डपंच समेत गांव के लोग गुरुवार को कलेक्ट्री पहुंचे। लोगों ने कलेक्ट्री के सामने अवैध अतिक्रमण को लेकर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि ग्राम पंचायत माडा में मुख्य आबादी भूमि खसरा नंबर 3039 रकबा 0.1000 है। इस खसरे में राधाकृष्ण मंदिर, माताजी मंदिर, महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, प्राइमरी भवन पुराना, सामुदायिक भवन ओर पार्क की भूमि है। ये पूरी जमीन गांव की सामूहिक है, लेकिन इस जमीन पर गांव के प्रभु पुत्र पाडजी लबाना, शंकर पुत्र पाडजी लबाना, प्रशांत पुत्र पाडजी लबाना की ओर से अवैध अतिक्रमण कर लिया है।

राशिफल शुक्रवार 4 अप्रैल, 2025

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, आर्द्रा नक्षत्र शनिवार प्रातः 5:32 तक, शोभन योग रात्रि 9:45 तक, गर करण प्रातः 8:57 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रात्रि 8:13 से आरम्भ होगी। आज से जैन ओली और दुर्गा पूजन (बंगाल) आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 7:51 तक, लाभ-अमृत 7:51 से 10:57 तक, शुभ 12:29 से 2:02 तक, चर 5:08 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:39

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आज मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मन में असंतोष बना रहेगा। आज स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आज संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बनते कार्य बिगड़ने का भय है। भावनात्मक कारणों से परेशानी हो सकती है।

धनु
घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मीन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 356 प्रभात जालोर, शुक्रवार 4 अप्रैल, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

एक ही झटके में ट्रम्प अमेरिका को 17वीं शताब्दी की सोच में ले गये

उस समय की सोच थी, आयात बुरा है, निर्यात अच्छा। अतः अपना सारा सामान निर्यात करो व सोना आयात करो

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। यूक्रेन वॉर की तरह किसी ने नहीं सोचा था कि रूस आक्रमण करने की योजना लागू कर देगा। किसी को भी यकीन नहीं था कि ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की जो धमकी दे रहे हैं वे उस पर अमल करेंगे पर 2 अप्रैल से वह लागू हो गई। उनकी घोषणा जितनी सोची गई थी वास्तव में उससे भी ज्यादा भयावह है।

डॉनल्ड ट्रंप का 2 अप्रैल का टैरिफ का फैसला, आशंकाओं से ज्यादा बुरा साबित हुआ। एक झटके में ही उन्होंने अमेरिका की व्यापार व्यवथा को 125 साल पीछे धकेल दिया है। नए टैरिफ के साथ अमेरिका 1900 के टैरिफ प्रणाली में पहुँच गया है।

यही नहीं ट्रंप के सोचने का तरीका भी बदल गया है।

दार्शनिक रूप से हमें उस युग में पहुंचा दिया गया, जब अर्थशास्त्री मानते थे कि निर्यात अच्छा है और आयात बुरा। इसलिए सब चीजों का निर्यात करो, सिर्फ गोल्ड का ही आयात करो, 17वीं सदी के दौर में जाने को बाध्य किया जा रहा है।

- **साथ ही, यह भी सच है कि ट्रम्प ने जो नया टैरिफ ऑर्डर पास किया, वह, जो आशंका थी, उससे भी ज्यादा सख्त व हानिकारक निकला, वाणिज्य व व्यापार की दृष्टि से।**
- **भारत से आये सामान पर ट्रम्प ने लगभग 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया और चीन से अमेरिका भेजे गये सामान पर 54 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।**
- **चीन पर बढ़ा हुआ टैरिफ ज्यादा दुखदायी इसलिये भी है, क्योंकि चीन की इकॉनमी एक्सपोर्ट पर आधारित है। उदाहरण के लिये, चीन में निर्मित ''स्टील'' का आधा माल ही चीन में खपता है, बाकी एक्सपोर्ट होना जरूरी है चीन की वाणिज्य नीति के अनुसार।**
- **दूसरी ओर, हालांकि, भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगी है, पर, भारत की जीडीपी का 2.2 प्रतिशत हिस्सा ही एक्सपोर्ट होता है। अतः भारत को इस बढ़े हुए टैरिफ का ज्यादा खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा।**
- **पर, कई देश, जिनका वाणिज्य केवल सामान के एक्सपोर्ट पर निर्भर है, जैसे बाँग्लादेश, की इकॉनमी अमेरिका को गारमैंट एक्सपोर्ट पर निर्भर है, पर फिर भी 34 प्रतिशत टैरिफ लगा है और अब तक बाँग्लादेश के सामान पर लगभग ज़ीरो प्रतिशत टैरिफ लगता था। अतः बाँग्लादेश के सामने भारी संकट है।**

वह व्यापारीवाद का सुनहरा युग था, जिस उस दौर के अर्थशास्त्री जीन बैपरिस्ट कोलबर्ट ने पेश किया था। वर्ष 1949 में अर्थशास्त्री सर जॉन क्लैयहम ने कोलबर्ट की किताब की समीक्षा कर उन्हें मूर्ख, तानाशाह व चिड़चिड़ा करार दिया था। यह बात ट्रंप के लिए भी सटीक टिप्पणी लगती है।

एक ही झटके में ट्रंप ने 2 अप्रैल को विश्व व्यापारिक संरचना और आर्थिक संबंधों को नष्ट कर दिया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने वर्षों में बड़ी सतर्कता से बनाए गए थे।

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन को समाप्त किया जा सकता है। देशों के बीच व्यापारिक विवाद सुलझाने का संगठन भी पुराना हो गया है। शिकायतें दर्ज करने का कोई मतलब नहीं रहा है। अगर विश्व की सबसे भी ताकतवर अर्थव्यवस्था उन देशों पर भारी टैरिफ लगा सकती है। जहाँ तो सबसे पसंदी राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित नियमानुसार व्यापार प्रणाली कहाँ रह जाती है।

वैश्विक व्यापार व्यवस्था के प्रशंको सादर के रखते है पर सवाल है कि 2 अप्रैल के बाद भारत का क्या होगा, सामान्य रूप से देखें तो गंभीर कुछ भी नहीं, पर, भारत के कुछ संवेदनशील क्षेत्र अवश्य प्रभावित होंगे, पर, आमतौर पर भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर ज़िंदा बम मामले में फैसला आज

जयपुर, 3 अप्रैल। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में 13 मई 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में शुक्रवार 4 अप्रैल को फैसला देगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक श्रवण कुमार ने मामले के चार आरोपी शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व सैफुर्रहमान के खिलाफ 112 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। वहीं करीब 1200 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपियों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए।

- **जयपुर में 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर ज़िंदा बम मिले थे।**

बचाव पक्ष ने 122 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपी पक्ष की ओर से अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले और पूर्व में जयपुर बम ब्लास्ट केस के तथ्य समान हैं। इन्हीं समान तथ्यों पर हाईकोर्ट आरोपियों को बरी कर चुका है। इस मामले में अभियोजन पक्ष यह भी पता नहीं कर पाया है कि साइकिल किसने रखी थी। वहीं चांदपोल गेट के बाहर किसी आरोपी की निशानदेही भी साबित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने राज्यसभा में बड़ी जोशीली बहस की वक्फ के विधेयक पर

विपक्ष के नेता ने सरकार पर ट्विटर (अब एक्स) पर आरोप लगाया कि यह विधेयक मुसलमानों को ''मार्जिनाइलाइज़'' करने का प्रयास है, उनके ''पर्सनल लॉज़'' तथा प्रॉपर्टी के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। केन्द्रीय संसदीय मामलात तथा अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ने आज इंडिया ब्लॉक के कड़े विरोध के बीच वक्फ अमेन्डमैंट बिल तथा मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल विचार करने तथा पारित होने के लिये राज्यसभा में पेश कर दिया।

लोकसभा में 12 घंटे तक चली बहस के बाद, यह बिल देर रात पारित हो गया था। इसके पक्ष में 288 तथा विरोध में 232 वोट पड़े थे। इस बिल के विरोध में सभी विपक्षी नेता एकजुट थे, जो आज की बँटी हुई राजनीति में एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना है।

बहस की प्रकृति एवं विषयवस्तु साफ तौर पर दर्शाती है कि कल ''धर्मनिरपेक्ष'' इंडिया ब्लॉक हिन्दुत्व ताकतों से टकराने के लिये कृतसंकल्प नज़र आया। जिनकी पूरी राजनीति हिन्दू-मुस्लिम विभाजन के चारों ओर घूम रही है। जहाँ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ''एक्स'' पर कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक मुस्लिमों को हाशिये पर पहुँचाने वाला, तथा पर्सनल लॉ और सम्पत्ति के अधिकारों को छीनने वाला हथियार एवं साधन है, वहीं, रिजिजू ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों के नियमन एवं प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करना है।

- **पर, संसदीय मामलों के मंत्री रिजीजू ने भी पुरजोर ढंग से विधेयक पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि विधेयक लाने का मकसद, उन मुद्दों व चुनौतियों का समाधान करना है, जो वक्फ की सम्पत्ति के प्रबंध व संचालन के दौरान सामने आई हैं।**
- **रिजीजू ने यह भी कहा कि यह विधेयक पिछली सरकारों के उन कामों को पूरा कर रहा है, जो अधूरे रह गये थे।**
- **रिजीजू के अनुसार, दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं कि अब यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि कोई सम्पत्ति वक्फ की है, उसका प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। पहले प्रावधान था कि अगर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की है तो उसे वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित कर दिया जाता था। अब नए विधेयक में यह प्रावधान हटा दिया गया है।**
- **संख्या बल के कारण संभावना यह है कि राज्यसभा में भी यह विधेयक पारित हो जायेगा।**

राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस, भाजपा तथा उसके मित्र दलों द्वारा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बम की धमकी ने जयपुर कलैक्ट्रेट खाली कराया

दो सौ कमरों की बम स्क्वॉड व इमरजेन्सी रैस्पॉन्स टीम द्वारा की गई जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

जयपुर, 3 अप्रैल। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर खाली करवाया गया। जानकारी के अनुसार, कलेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी की सरकारी आईडी पर धमकी का ईमेल आया था। धमकी वाले ईमेल की जानकारी कलेक्टर ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को दी। इसके बाद आनन-फानन में पूरे परिसर से लोगों को बाहर निकाला गया। करीब दो सौ कमरों की जांच के लिए बम स्क्वॉड और इमरजेंसी रैस्पॉन्स टीम को भी बुलाया गया। हालांकि, सर्च के दौरान किसी भी एजेंसी को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बड़ी संख्या में पुलिस के मौजूद रहने के साथ ही, कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों के बाहर निकलने से कलेक्ट्रेट के आस-पास जाम के हालात हो गए। वाहनों की लम्बी कतारें लग गईं। पुलिस की जांच खत्म होने के बाद ही यातायात सामान्य हो पाया।

- **बड़ी संख्या में पुलिस तथा कलैक्ट्रेट के सारे कर्मचारियों के बाहर होने के कारण पूरे क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी।**
- **धमकी का ई-मेल कलैक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी की सरकारी आईडी पर आया।**

जानकारी के अनुसार, सभी कर्मचारी अपने समय के अनुसार जयपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए थे। सुबह सामान्य दिनों की तरह कामकाज चल रहा था। अचानक 11.30 बजे के आसपास शोर मचने लगा। सभी को परिसर खाली करने के लिए कहा गया। इसी के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अंदर पहुंचने लगे थे। जब कर्मचारी बाहर निकले तो पता चला कि कलेक्टर के पास बम की धमकी का ईमेल आया है। दोपहर 2 बजे तक भी बिल्डिंग परिसर में बम स्क्वॉड की टीमें मौजूद थीं।

पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि जयपुर कलेक्टर ऑफिस के मेल आईडी पर यह मेल आया कि ''2-जी मामले में सवुक्कु शंकर के साथ हुए अनुचित व्यवहार और सादिक बलवा की हिरासत में हुई मौत का बदला लेने के लिए बम रखा गया है। हम सुरक्षा एजेंसी को भगवान के नाम पर रैस्क्यू ऑपरेशन चलाने का चैलेंज देते हैं। बम वीकेंड पर पहले से ही आज के लिए लगा दिया गया था, जो अन्ना यूनिवर्सिटी एमआईटी कैंपस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तैयार किया गया है। आज इस बम से धमाका करेंगे। हमारा लक्ष्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान से ड्रोन से आई ढाई करोड़ की हेरोइन जब्त

श्रीगंगानगर, 3 अप्रैल (निसं) जिले के श्रीकरणपुर बॉर्डर पर बीएसएफ (बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स) ने पाकिस्तान से आई हेरोइन की भारी खेप जब्त की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 11 एफ गांव में रात साढ़े 11 से 12 बजे के बीच वहाँ ड्रोन की गतिविधि देखी गई। बीएसएफ जवानों ने तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचना दी। एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय करने पर ड्रोन वापस नहीं जा सका और वहीं गिर गया। ड्रोन से 500 ग्राम हेरोइन गिराई गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत ढाई करोड़ रुपए आंकी गई है।

- **श्रीकरणपुर बॉर्डर पर बीएसएफ ने देर रात हेरोइन का पैकेट व ड्रोन बरामद किया।**

बीएसएफ ने श्रीकरणपुर पुलिस को सूचना दी। सीओ संजीव चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में एक पीले रंग का हेरोइन का पैकेट और ड्रोन बरामद किया गया। सुबह भी बीएसएफ और पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था, लेकिन इसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डी.एम.के. वक्फ बोर्ड विधेयक को न्यायालय में चुनौती देगा

अगले वर्ष तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्टालिन अपने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में संगठित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। सैक्युलर ब्लॉक में खड़ा आखिरी आदमी, जो केन्द्र सरकार और भाजपा से मुकाबला कर रहा है, वे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। दोबारा चुनाव जीतने के लिए वे इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं।

अब उन्होंने वक्फ बिल पर अपने आक्रामक रुख से नई गुगली उछाली है कि वे वक्फ बिल को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने इस बारे में तमिलनाडु विधानसभा में घोषणा की।

स्टालिन और द्रमुक पहले राजनेता एवं राजनैतिक दल हैं, जिन्होंने विवादास्पद वक्फ संशोधन का खुले आम विरोध किया है,वो भी राज्य विधानसभा में। वक्फ बिल लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा।

- **इससे पहले, चुनाव की तैयारी के तहत ही शायद, स्टालिन कई जज़्बाती मुद्दों को, जैसे नई शिक्षा नीति, डीलिमिटेशन और काचातीवू द्वीप के मामले पर जमकर बोलते रहे हैं।**

द्रमुक ने संसद के भीतर और बाहर भी वक्फ बिल का विरोध किया। मुख्यमंत्री खुद वक्फ बिल के विरोध में उतर आए हैं और वे इसे एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, जो राज्य में अल्पसंख्यक मतों को द्रमुक के पक्ष में एकजुट कर देगा। वे पहले ही तीन भावनात्मक मुद्दे उठा चुके हैं - परिसीमन, भाषा और काचातीवू द्वीप और अब इसमें वक्फ बिल के आ जाने से उनका पलड़ा भारी हो रहा है।

इस स्थिति ने अन्नाद्रमुक को मुश्किल में डाल दिया है, जो विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन की तैयारी में है। यद्यपि यह गठबंधन भाजपा को भारी लाभ पहुंचा सकता है, पर अन्नाद्रमुक को और ज्यादा कमज़ोर कर सकता है। अन्नामलाई के नेतृत्व में राज्य में भाजपा की ताकत बढ़ी है। पर इससे अन्नाद्रमुक कमज़ोर हुई है। यही नहीं, भाजपा ने अपने कठपुतली नेताओं के जरिए अन्नाद्रमुक को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया है। अटकलें थीं कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री व अन्नाद्रमुक से अलग हुए गुट के नेता ओ पन्नीरसेल्वम का समर्थन किया था। भाजपा की कोशिश है कि दोनों गुट एक हो जाएं।

पर लम्बी कानूनी व राजनैतिक लड़ाई के बाद ओ पन्नीरसेल्वम को निकाल पाने में सफल रहने के बाद, अन्नाद्रमुक के वर्तमान अध्यक्ष ई. पलानीस्वामी उन्हें वापस लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने पन्नीरसेल्वम को वापस लेने से मना कर दिया, यही नहीं लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने भाजपा से सम्बंध तोड़ दिया था।

पर विपक्ष के वोट बंटने से लोकसभा चुनाव में द्रमुक को एकतरफा जीत मिली। इसलिए एक बार फिर अन्नाद्रमुक और भाजपा गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं। पर स्टालिन एक के बाद एक गुगली फेंक रहे हैं और इस बार उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई की घोषणा कर अन्नाद्रमुक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अन्नाद्रमुक का भाजपा के साथ नज़र आना उसके अल्पसंख्यक वोट को प्रभावित कर सकता है। तमिलनाडु में 6 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और वह एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है।

खंडवा में कुएं में जहरीली गैस से 8 मरे

खंडवा, 03 अप्रैल। खंडवा में एक कुएं में जहरीली गैस से दम घुटने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 8 शव कुएं से बाहर निकाल लिए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस, प्रशासन और एसडीईआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।

- **गणगौर विसर्जन के लिए कुएं की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ।**

ये घटना गुरुवार शाम को जिले के छैगांवमाखन क्षेत्र के कोंडावत गांव की है। बताया जा रहा है कि गणगौर विसर्जन को लेकर अर्जुन नाम का शख्स कुएं की सफाई करने उतरा, जो जहरीली गैस के कारण बेसुध होकर कुएं में जमे दलदल में डूब गया। उसे बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 7 और लोग कुएं में उतरे। ये सब भी जहरीली गैस के कारण दम घुटने से डूब गए और इनकी मौत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अमेरिका छींकता है, तो विश्व को ज़ुकाम हो जाता है'

अमेरिका ने बेरहमी से सभी देशों पर, नया टैरिफ लागू किया, 2 अप्रैल से

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। संपूर्ण विश्व एक बार फिर हिल गया, जब सदियों पुरानी यह कहावत सच साबित हुई कि ''जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है।'' इस बार यह छींक फुसफुसाहट नहीं, बल्कि आसमान से गिरी बिजली की गरज के रुप में आई है- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की, रैसिप्रोकल टैरिफ (प्रत्युत्तर शुल्क) लगाने की घोषणा ने विश्व के बाज़ारों को हिला दिया। ट्रंप ने एक ही झटके में एक आर्थिक तूफान खड़ा कर दिया और कसम खाई कि वे, अपने व्यापारिक साझेदारों द्वारा अमेरिका से लिए जाने वाले टैरिफ का लगभग आधा टैरिफ लगाएंगे।

सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है भारत, जो अमेरिका को किए जाने वाले अपने निर्यात पर 26 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहा है। यह कदम ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके द्वारा वे अमेरिकी टैरिफ को अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ के समानांतर बनाना चाहते हैं। इसका लक्ष्य है, अमेरिका की दृष्टि से एक न्यायसंगत व्यापारिक परिदृश्य तैयार करना। भारत, जिसने वर्षों से अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक साझेदारी बनाकर रखी है, को अब अपने प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर गंभीर दबाव का सामना करना पड़ेगा।

बुधवार को वाइट हाउस के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, ''भारत बहुत, बहुत सख़्त है, बहुत, बहुत सख़्त है। प्रधानमंत्री अभी-अभी गए हैं, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन, आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52 प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) वसूलते हैं।''

तथापि, मोदी के साथ उनके ''अच्छे व्यक्तिगत संबंधों'' ने उन्हें भारत पर उच्च शुल्क लगाने से नहीं रोका।

ट्रंप के इस कदम पर भारत की अधिकारिक प्रतिक्रिया संयमित रही। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ''इसका मिलाजुला असर होगा, यह भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है।'' जबकि, निर्यातकों को इस बात से सांत्वना मिली कि यह शुल्क भारत के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

- **अमेरिका की नई टैरिफ रणनीति है, जो देश अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाते हैं, उसका आधा टैरिफ अमेरिका उन देशों से अमेरिका निर्यात किये गये सामान पर लगायेगा।**
- **उदाहरण के लिये, वियतनाम पर 46 प्रतिशत, ताईवान पर 32 प्रतिशत, जापान पर 24 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत, थाईलैण्ड पर 36 प्रतिशत लगायेगा अमेरिका।**
- **यूरोप पर भी 20 प्रतिशत टैरिफ लगेगा तथा यूरोपीय देश अपनी आर्थिक व वाणिज्य रणनीति तैयार कर रहे हैं, टैरिफ से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिये।**
- **ट्रम्प का कहना है, भारत, अमेरिकी सामान पर 52 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। अतः अमेरिका अब भारतीय माल पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा।**
- **चीन अमेरिकी सामान पर 67 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। अतः चीन में निर्मित सामान पर अमेरिका 34 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा।**

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि चीन अमेरिकी माल पर 67 प्रतिशत टैरिफ लगाता है तो प्रतिक्रिया में अमेरिका चीनी माल पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा।

कुछ ही दिन पहले, यू.एस. ट्रेड रिप्रैज़ेन्टेटिव (यू.एस.टी.आर.) ने 2025 की नैशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट (एन.टी.ई.) जारी की, जिसमें कहा गया है कि भारत, कृषि उत्पादों, दवा उत्पादन और मादक पेय पदार्थों जैसी अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगाता है, इसके अलावा गैर टैरिफ बाधाएं भी लगाता है।''

अमेरिका की टैरिफ रणनीति केवल भारत को ही प्रभावित नहीं करती है। वियतनाम (46 प्रतिशत), ताईवान (32 प्रतिशत), जापान (24 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (25 प्रतिशत) और थाईलैण्ड (36 प्रतिशत) जैसे देश भी इसके परिणाम का आकलन कर रहे हैं। बीस प्रतिशत टैरिफ के साथ यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव की संभावना से अपनी आर्थिक रणनीतियों का पूनर्मूल्यांकन का रहा है।

भारत पर लगाया गया इस स्तर का शुल्क, दोनों देशों के बीच बड़ी मेहनत से बनाए गए व्यापार संबंधों पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करेगा। अमेरिका के साथ मजबूत व्यापार साझेदारी का आनंद ले रहा भारत, अब इस चुनौती का सामना कर रहा है कि उसके प्रमुख निर्यात क्षेत्र उच्च लागत और अमेरिकी बाज़ारों में घटती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावित होंगे। भारत का आई.टी. सैक्टर, जिसमें टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेज़ (टी.सी.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वनरक्षक भर्ती, फरार आरोपी पर 50 हजार का ईनाम घोषित

जयपुर, 3 अप्रैल। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में वांछित फरार बदमाश जबराराम जाट पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। आरोपी बाड़मेर में ग्रेड थर्ड टीचर के पद पर कार्यरत है और वन रक्षक भर्ती मामले में फरार चल रहा है। एसओजी की ओर से उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

- **आरोपी जबराराम बाड़मेर में थर्ड ग्रेड टीचर है और अभी तक पकड़ में नहीं आया है।**

एडीजी (एसओजी व एटीएस) वी.के. सिंह ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक मामले में साल-2024 में बांसवाड़ा के राजतलाब थाने में मामला दर्ज हुआ था। वन रक्षक भर्ती मामले की जांच में जबराराम जाट निवासी कालवा पचपदरा बालोतरा भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बोनस देने की मांग को लेकर श्रमिकों ने संगम इंडिया लिमिटेड में उत्पात मचाया

भीड़ को तितर-भीतर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, कई श्रमिक घायल

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित संगम इंडिया लिमिटेड में गुरुवार को श्रमिकों ने बोनस देने की मांग को लेकर उत्पात मचाया। फैक्टरी और तैनात पुलिस की डायल 112 जीप में तोड़फोड़ किए जाने से माहौल गरमा गया। अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। उधर, उत्पात और पथराव को लेकर पुलिस ने पांच लोगों को डिटेन कर लिया है। इस संबंध में पुलिस प्रकरण भी दर्ज कर रही है।

- **उत्पात और पथराव को लेकर पुलिस ने पांच लोगों को डिटेन किया**
- **आरोप है कि प्रबंधन ने बोनस सभी श्रमिकों को न देकर आधे श्रमिकों को ही दिया था**

हमीरगढ़ क्षेत्र स्थित संगम इंडिया लि. में श्रमिकों ने बोनस देने की मांग को लेकर उत्पात मचाया और पुलिस जीप में तोड़फोड़ कर दी।

हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि स्वरुपगंज क्षेत्र स्थित संगम इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन से श्रमिकों से 3-3 हजार रुपये बोनस देने का वादा किया था। आरोप है कि प्रबंधन ने यह बोनस सभी श्रमिकों को न देकर आधे श्रमिकों को ही दिया, जबकि शेष आधे श्रमिक बोनस नहीं मिलने से नाराज थे। इसी को लेकर गुरुवार को नाराज श्रमिकों ने फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन व हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर पुलिस वाहन डायल 112 मौके पर पहुंचा। फैक्ट्री प्रबंधन की मांगों पर अनदेखी से नजर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन श्रमिकों ने फैक्ट्री के साथ ही वहां खड़े पुलिस के डायल 112 वाहन पर भी पथराव कर दिया, जिससे वाहन के शीशे टूट गये। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही एएसपी, डीएसपी व थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश कर शांत करवाया। इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसमें आधा दर्जन श्रमिक घायल हो गए। उधर, पुलिस ने फैक्टरी और पुलिस वाहन पर पत्थर फैंकने के मामले में मुकदमा दर्ज कर पांच संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है।

कुएं से नहीं मिला वृद्ध का शव, पांच दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

वृद्ध के शव को तलाशने के लिये पांच एलएनटी मशीनें, पांच पंप, जनरेटर काम में लिए जा रहे हैं

टोंक, (निसं)। पीपलू थाना क्षेत्र के जंवाली गांव में 29 मार्च से लापता वृद्ध का शव गुरुवार को भी कोई सुराग नहीं लगा, उसकी तलाश में 5 एलएनटी मशीनें, 5 पानी निकालने के पंप, जनरेटर काम में लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद गुरुवार दोपहर तक भी लापता वृद्ध नहीं मिल पाया है, इसकी प्रमुख वजह कुएं में पानी का रिसाव तेज गति से होने और कुएं के निचले हिस्से में मिट्टी ढहने से रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो रहा है।

- **कुएं में पानी का रिसाव तेज होने और निचले हिस्से में मिट्टी ढहने से रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो रहा है**

प्राप्त जानकारी के अनुसार जंवाली ग्राम निवासी कैलाश (65) पुत्र प्रताप यादव जो 29 मार्च को भैंस को चराने के लिए खेतों की ओर गया था, जो शाम को लौटकर नहीं आया तो परिजनों अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला, जिसकी 30 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि लापता व्यक्ति का साफा गांव के सहोदरा नदी के पास स्थित करीब 40 फीट गहरे कुएं में मिला है, वहीं कुएं के आसपास ही उनकी लकड़ी व पानी की बोतल भी मिली है। पुलिस प्रशासन द्वारा पांच दिन तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वही 2 अप्रैल को कुएं के बराबर में 3 जेसीबी एक लोडर व एक एलएनटी मशीन से खुदाई शुरू कर गड्डा बनाया, लेकिन निचले हिस्से में मिट्टी ढहने और पानी का रिसाव ज्यादा होने से रेस्क्यू टीम कुएं के बीचों-बीच पड़े मलबे को हटा नहीं पा रही है।

कार से टकराकर नदी में गिरा ट्रक, 12 घायल

पाली में कार से टकराकर ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर करीब 40 फीट नीचे नदी में गिर गया।

पाली, (नि.सं.)। पाली में गुरुवार दोपहर को कार से टकराकर ट्रक असंतुलित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर करीब 40 फीट नीचे नदी में गिर गया। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल लाया गया। वहां उनका उपचार जारी है।

- **घायलों को बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया**

सदर थाने के सब इंस्पेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि पाली-जोधपुर हाइवे पर दोपहर को चारे से भरा ट्रक पूनायता औद्योगिक क्षेत्र के निकट हाइवे पर असंतुलित होकर पलटकर नदी में गिर गया। इस हादसे करीब 11 जने घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। पाली से जोधपुर की तरफ जाते समय ये हादसा हुआ। इस हादसे में बाड़मेर जिले के (अज़बानी) बूथिया निवासी मोहम्मद पुत्र इलियास खान, रसूल पुत्र पीनल खान, रोशन पुत्र अमर खान, आमीन पुत्र नूरा खान, अबन खान, असकर खान, अकबर, कालू खान, इशाक खान, इरफान और शकूर खान घायल हो गये। सभी घायल रिश्तेदार हैं और चारा बेचने के काम से जुड़े हैं।

एनडीपीएस मामले में दो व्यक्तियों को 14-14 साल का कारावास

तारानगर, (निसं)। तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने अभियुक्त हरियाणा के बलजीत सिंह व अजमेर सिंह को 10 साल पहले दर्ज एनडीपीएस मामले में 14-14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

- **200 किलो डोडा-पोस्त चूरा बरामद हुआ था**

अपर लोक सरकार की ओर पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज स्वामी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को तारानगर क्षेत्र के साहवा सड़क के पास से गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 200 किलो मादक पदार्थ (डोडा-पोस्त चूरा) बरामद हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, अदालत ने आरोप तय किये। स्वामी ने आगे बताया कि न्यायालय के समक्ष तर्क दिये कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित किया है। उन्होंने दोषियों को एक अनुकरणीय सजा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि नशा देश के युवाओं को नष्ट कर रहा है जिस पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा द्वारा आरोपियों को प्रत्येक को धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में 14 साल के कठोर कारावास व 1,50,000 रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड में अतिरिक्त दो वर्ष के साधारण कारावास धारा 468 भा.दं.सं. के लिए 5 साल का कठोर कारावास व 20,000 रुपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड में तीन माह के साधारण कारावास व धारा 471 भा.दं.सं. में एक साल के कठोर कारावास 20,000 रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड में तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुना कर जेल भेजा।

रिश्वतखोर दो कांस्टेबल को न्यायालय ने जेल भेजा

कोटा, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी टीम ने मारपीट के मामले में मदद करने की एवज में दस हजार की रिश्वत लेते पकड़े गये दादाबाड़ी के दोनों कांस्टेबलों को गुरूवार को एसीबी ने न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों कांस्टेबल बनवीर आचार्य व मनीष जांगिड़ को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

- **मारपीट के मामले में मदद करने की एवज में दस हजार की रिश्वत ली थी**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा (एसीबी) टीम ने परिवादी की शिकायत पर बुधवार रात्रि को कार्यवाही करते हुए दादाबाड़ी थाने के दो कांस्टेबल बनवीर आचार्य व मनीष जांगिड़ को थाने में दर्ज मारपीट के मामले में मदद करने की एवज में 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एसीबी के एडीशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि एसीबी में परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके बेटों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज था। बेटों को बचाने की एवज में दादाबाड़ी थाने के दो कांस्टेबल बनवीर आचार्य व मनीष जांगिड़ 30 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत का सत्यापन कराने के बाद सत्यपान में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। एडीशनल एसपी एसीबी ने बताया कि पुष्टि के बाद टीम ने जाल बिछाया और बुधवार रात्रि को ट्रेप की कार्यवाही करते हुए थाने से कुछ दूरी पर रामधाम के समीप कांस्ट्रेबल बनवीर व मनीष को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। मामले में सामने आया कि दादाबाड़ी थाने में मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें आरोपी को बचाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने बुधवार को रिश्वत लेते पकड़े गये दोनों कांस्टेबलों को गुरूवार को न्यायालय में पेश किया।

क्रशर पर मारपीट करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

खेतड़ी, (निसं)। मेहाड़ा पुलिस ने दुधवा में क्रशर पर मारपीट कर मंथली की डिमांड करने की वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

- **वारदात में इस्तेमाल बाइक व बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया**
- **वारदात के मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस**

मेहाड़ा पुलिस ने क्रशर पर मारपीट करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने वारदात में काम में ली गई बाइक व बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है।

थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि 27 मार्च को राजपाल पुत्र नागरमल सैनी निवासी मोडी हाल क्रशर पार्टनर अग्रवाल ग्रीट उद्योग दुधवा ने रिपोर्ट पेश की कि उसके क्रशर पर करीब तीन बजे एक बाइक आपाची आई, जिस पर तीन आदमी आए। तीनों के हाथों में हथियार थे जो तीनों बाइक से उतरते ही बाहर बैठे मुनीम कैलाश के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व क्रशर को बंद करने की धमकी देकर बोले कि क्रशर चलाना है तो 20 हजार रुपए मंथली देने होंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी भजनाराम के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश में आस-पास रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खगांले गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आस-पास में संभावित स्थानों हरियाणा में नांगल चौधरी, महेन्द्रगढ़, नारनौल, बहरोड, कोटपुतली, प्रागपुरा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ व अहमदाबाद गुजरात में की गई व संदिग्धों से पूछताछ की गई। टीम द्वारा आरोपियों का लगातार पीछा कर अथक प्रयास से मुख्य आरोपी हीरा गुर्जर, बादल मीणा का सहयोग करने वाले थली निवासी सचिन पुत्र शीशराम व भोदन निवासी दीपक राठी पुत्र देवेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बाइक व बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस वारदात के मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इस दौरान टीम में थानाधिकारी भजनाराम, एचसी विक्रम, कांस्टेबल रोहिताश, कर्मपाल, प्रमोद, पवन कुमार, पूनम आदि शामिल थे।

तीन किलो डोडा-पोस्त छिलका जब्त, दो गिरफ्तार

दूदू पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कारों को पकड़ा।

सांभरझील, (निसं)। दूदू पुलिस ने नशा कारोबार में लिप्त दो जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 किलो 72 ग्राम डोडा पोस्त छिलका जब्त किया है।

थाना अधिकारी दूदू मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि तेतरवालों की ढाणी के पास, एचपी पैट्रोल पम्प, एनएच 48 तन पड़ासोली पर दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में मोटरसाइकिल लेकर खड़े हैं। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम तुरन्त मौके पर पहुंची और देखा तो बताये गये हुलिये के दो व्यक्ति मय मोटरसाइकिल के साथ खड़े दिखाई दिये जिनका नाम-पता पूछा तो एक ने अपना नाम जीतराम गुर्जर व दूसरे ने प्रदीप राजपुरोहित बताया जिनको डिटेन कर कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त छिलका तथा मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को जब्त कर गिरफ्तार किया। डोडा-पोस्त की वर्तमान में अनुमानित बाजार की कीमत करीबन 55 हजार 800 रूपये आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। आरोपी मादक पदार्थ कहां से लेकर आये थे तथा किन-किन जगहों पर सप्लाई करने की फिराक में थे इसके संबंध मे गहनता से अनुसंधान किया जायेगा। गिरफ्तार आरोपी कदमपुरा थाना बांदरसिंदरी जिला अजमेर व प्रेमनगर, केकडी थाना केकडी जिला अजमेर का रहने वाला है।

मारपीट मामले में फरार तीन आरोपी गिरफ्तार

नारायणपुर, (निसं)। थाना क्षेत्र के मालोड़ी की ढाणी में रास्ते को लेकर हुए विवाद में गंभीर मारपीट के मामले में पुलिस ने छह महीने से फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

थानाधिकारी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि 23 सितंबर 2024 को रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जानलेवा हमला किया था। मामले में पहले ही दोनों पक्षों से दो-दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। बुधवार देर शाम को पुलिस ने टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल मालोड़ी की ढाणी निवासी दुर्गा राम पुत्र सोहन लाल सैनी, लहरी राम पुत्र चौथूराम सैनी और रतन लाल पुत्र चौथमल सैनी को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार यह मामला लंबे समय से लंबित था और आरोपियों की तलाश जारी थी। आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी हैं।

सूरतगढ़ में सैन्य छावनी में जवान की मौत

सूरतगढ़, (निसं)। सैन्य छावनी में सेना के एक जवान की मौत का मामला सामने आया है। मृतक दीपक यादव (31) पुत्र वकील यादव, निवासी गांव दलछपरा, थाना रेवती, जिला बलिया (बिहार) था, जो फील्ड हॉस्पिटल मिलिट्री कैंट में तैनात था। सुबह पास ही स्थित मंदिर के पुजारी ने एमटी शेड के नीचे जवान का शव फंदे से लटका देखा। उसने तुरंत सेना के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को मिलिट्री हॉस्पिटल में रखवा दिया। थाना सदर के एएसआई सोहनलाल ने बताया कि जवान के आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर वे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि, इस मामले को लेकर सेना के अधिकारियों ने अब तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। बताया जा रहा है कि दीपक यादव हाल ही में 20 मार्च को अपने गांव से छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटा था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है।

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2022)
राजीव गांधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर-305001 (राज.)

दिनांक : 02.04.2025

रीट-2022 परीक्षार्थी को मूल ओ.एम.आर की प्रति यदि आवश्यक है तो दिनांक-17.04.2025 तक बोर्ड कार्यालय मे 300/- रूपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ रजिस्टर्ड डाक से आवेदन या व्यक्तिशः प्राप्त कर सकते है। अन्तिम दिनांक के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

समन्वयक

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा
रावतभाटारोड़, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सामने, जिला कोटा (राज.) पिन-324010
Phone No. 0744-2470723 Email:-dcfmnp.kot.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक: एफ () पर्यटन/उवस/मु.रा.उ/2024-25/2740 दिनांक : 1/4/2025
विज्ञप्ति-02/2025-28
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में पर्यटक वाहनों के पंजीकरण हेतु
RFP (Request for proposall)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा के बफर जोन के अनुमत मार्गों पर पर्यटकों को भ्रमण कराने हेतु वाहनों के पंजीकरण वर्ष 2025-26 हेतु सूचना प्रसारित की जाती है। जिसकी विस्तृत शर्तें वेबपोर्टल www.spp.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय समय में इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।
RFP Code:-FOR 2526RF0001
(मुथु एस)
DIPR/C/4650/2025 उप वन संरक्षक (वन्यजीव), मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा

OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENIGNEER, PWD, ZONE BIKANER
No:- 3687 Dt.:- 30.03.25
NIB CODE :- PWD 2425A4862
NIB NO. 03/2024-25
Bid for 01 No. RUB works Year 2024-25 Sanctioned are invited from interested bidders upto 6.00 PM dt. 22.04.2025 (tuesday) Other particulars of the bid may be visited on the procurment portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state and DIPR department website. The aporoximate values of the procument is Rs. 496.00 LAKHS
UBN Code No. : PWD2425WSOB17446
Superintending engineer, PWD, Circle Bikaner
DIPR/C/4637/2025

राजस्थान-सरकार
कार्यालय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी राजकीय जिला चिकित्सालय नाथद्वारा
क्रमांकः-पीएमलो/लेखा/2024-25/606 दिनांकः-28/03/2025
निविदा आमंत्रण सूचना
श्री गोवेर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय नाथद्वारा द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न सारणीनुसार कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जिसका विस्तृत विवरण राजकीय वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर देख जा सकता है।

क्रसं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	युबीएन नंबर
1	मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अंतर्गत कन्जुमेंबल रीएजेंट एवं आवश्यक सामग्री।	55 लाख	MHS2425RLOBO5819
2	आइएचएमएच पर्ची प्रिंटिंग एवं अन्य प्रिंटिंग कार्य।	05 लाख	MHS2425RLOBO5821
3	जनरल, स्टेशनरी आइटम्स एवं अन्य आवश्यम सामग्री	04 लाख	MHS2425RLOBO5820
4	मानव संसाधन आपूर्ति	120 लाख	MHS2425RLOBO5818
5	कंप्यूटर प्रिंटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स वार्षिक रखरखाव कार्य	04 लाख	MHS2425RLOBO5817

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं सचिव
DIPR/C/4612/2025 रामेरिसो राजकीय जिला चिकित्सालय, नाथद्वारा

अजमेर नगर निगम ने 164 अस्थाई सफाई कर्मचारियों को काम से निकाला

अजमेर, (कासं)। नगर निगम अजमेर सफाई ठेके का बजट कम करने जा रहा है, इसके तहत 164 अस्थाई सफाई कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। गुस्साए कर्मचारियों ने गुरुवार को निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

अस्थाई सफाई कर्मचारी इंद्रा ने बताया कि निगम में करीब दस से बीस साल तक समाज के कई लोग ठेका प्रथा पर काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, लेकिन एकाएक निगम प्रशासन ने एक साथ छह वार्डों में काम करने वाले 164 ठेकाकर्मियों को बाहर कर दिया है। ऐसे में उनके परिवार के समक्ष भरण-पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। एकाएक उन्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। एक ओर महंगाई चरम पर है, वहीं निगम ने उन्हें बेरोजगार कर सड़क पर ला दिया है।

अजमेर निगम परिसर में अस्थाई सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।

- **अस्थाई सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी**
- **दस से बीस साल तक कई लोग ठेका प्रथा पर काम कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे**
- **चौबीस घंटे में हटाए गए कर्मचारियों को काम पर वापस नहीं लिया तो सभी ठेका वार्डों में हड़ताल की चेतावनी दी**

सन्नी गोयर ने बताया कि पिछले दिनों मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था, लेकिन निगम प्रशासन ने झूठे आश्वासन देकर हड़ताल को समाप्त कर दिया। ठेकाकर्मी जब काम पर लौटे तो कुछ ही दिनों बाद छह वार्डों से कर्मचारियों को निकालकर उनके हितों पर कुठाराघात किया है। गोयर ने चेतावनी दी है कि चौबीस घंटे के भीतर निगम प्रशासन ने यदि हटाए गए 164 कर्मचारियों को काम पर वापस नहीं लिया तो सभी ठेका वार्डों में हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले वाहन एकाएक खराब हो गए। ठेकेदार ने चालीस वाहनों के खराब होने का हवाला देते हुए उनकी हाजरी नहीं लगाई, उन्होंने आशंका जताई है कि निगम प्रशासन एक-एक कर सभी ठेका कर्मियों को निकालने में लगा हुआ है।

पक्के वार्डों से समायोजित किए सफाईकर्मी :-निगम सूत्रों के अनुसार अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में कच्चे और पक्के वार्ड निर्धारित किए गए हैं। पक्के वार्डों में निगम के स्थाई कर्मचारी जबकि कच्चे वार्डों में अस्थाई कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं। पिछले दिनों सफाई के बजट को काम करते हुए निगम ने कच्चे वार्डों को पक्के वार्डों में बदलते हुए पक्के वार्डों से पांच-पांच कर्मचारियों को हटा कर नए बनाए गए वार्डों में समायोजित किया गया है। ऐसे में इन वार्डों में काम कर रहे अस्थाई सफाई कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया है।

सरकारी योजनाओं का लाभ देने व समस्याओं का समाधान करने के निर्देश

जालोर के पास हरजी में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में कलैक्टर डॉ.प्रदीप के. गावंडे ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं, परिवेदनाओं के निवारण, सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुरूवार को जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिनमें आमजन की परिवेदनाएं प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने हरजी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित पंचायत स्तरीय जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ ही जनता की समस्याओं पर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए परिवादों के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, सड़क, पंचायतीराज सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवाद प्रस्तुत हुए जिनकी सुनवाई करते हुए जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने विभिन्न परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया तथा शेष प्रकरण राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज कर निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकारी देकर इसका लाभ उठाने की बात कही। वहीजनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित केन्द्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर आहोर उपखण्ड अधिकारी सांवरमल रैगर, आहोर तहसीलदार मोहित आशिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

जिला परिषद् की विशेष बैठक 7 को

जालोर जिला परिषद की साधारण सभा की विशेष बैठक जिला प्रमुख राजेश कुमार की अध्यक्षता में 7 अप्रेल को दोपहर 12.30 बजे जिला परिषद सभा भवन में आयोजित की जायेगी।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर राजोरा ने बताया कि विशेष बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चतुर्थ के तहत ऑल वेदर रोड़ कनेक्टिविटी हेतु डी.आर.आर.पी. केन्डीडेट रोड़ एवं सी.यू.सी.पी.एल. के प्रस्तावों का अनुमोदन सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।

दिशा समिति की बैठक 8 को

जालोर-सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी की अध्यक्षता में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ''दिशा समिति'' की बैठक 8 अप्रेल को प्रातः 11.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी जिसमें विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की जायेगी।

यह जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर राजोरा ने दी।

डिस्कॉम कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया

जालोर में डिस्कॉम कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। जालोर में डिस्काम कर्मचारियो ने गुरुवार को निजीकरण के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौपा। उक्त ज्ञापन में कर्मचारियो ने निजीकरण का विरोध जताया है।

विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण निगम में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं एवं मॉडल के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने के लिए राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बेनर तले विद्युत विभाग में निजीकरण का विरोध का ज्ञापन दिया।

जिलाध्यक्ष राजस्थान विद्युत लेखा संघ विनोद आर्य, प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन राजस्थान इंटक खंड अध्यक्ष नवरतन मल कुमावत, अमृत सिंह जिला महामंत्री भारतीय मजदूर संघ, दिलीप मकवाना जिलाध्यक्ष राजस्थान राज्य विद्युत मंत्रालयिक संघ, नरेश गुर्जर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन, बिशन सिंह, भंवर सिंह देवडा, नेकी राम, मोती लाल सुथार, आशीष कुमार तिवारी, अश्वनी कुमार, विजय कुमार, जितेंद्र गर्ग, दिनेश चंद मीणा, शेर सिंह मीणा, मिश्रीमल, शिवेंद्र अग्रवाल, किरण खत्री, सुनील कुमार, मनीराम, नरेश सिंह बैरवा, मनीष सेन, श्रीमती सीता, भेरू सिंह , मुकेश कुमार मेहरा, पिंटू सिंह, मुस्ताक दीन, हेमराज बैरवा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।

लायंस क्लब के प्रांतपाल ने कार्यों की समीक्षा की

जालोर में प्रांतपाल लॉयन श्याम सुन्दर का लायंस क्लब अध्यक्ष कालूराज मेहता व सचिव दीपेश सिद्धावत की मौजूदगी में अभिनंदन किया। फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। लायंस क्लब के प्रांतपाल लॉयन श्याम सुंदर खत्री अपनी आधिकारिक यात्रा पर बुधवार शाम को जालोर पहुंचे।

जालोर पहुंचने पर संगठन पदाधिकारियों ने उनका लायंस क्लब अध्यक्ष कालूराज मेहता व सचिव दीपेश सिद्धावत की मौजूदगी में अभिनंदन किया।

इस दौरान शहर के महिला कॉलेज के सामने स्थित होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांतपाल ने संगठन के कार्यों की समीक्षा की।

साथ ही कहा लायंस क्लब जनहित के कार्यों को सर्वोपरि मानते हुए राहत के कार्य करता है।

उन्होंने संगठन के स्थानीय पदाधिकारियों के कार्यों की तारीफ की। साथ ही जनहित के कार्यों की कडी में और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए संगठन पदाधिकारियों को प्रेरित किया। उन्होंने आगामी दिनों में गर्मी के मौसम में सामाजिक सरोकार के कार्यों के लिए भी क्लब पदाधिकारियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान कोषाध्यक्ष लॉयन श्याम सुंदर गोयल ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।

सचिव दीपेश सिद्धावत ने लायंस क्लब की ओर से आयोजित नेत्र जांच शिविर और अन्य गतिविधियों से प्रांतपाल को अवगत करवाया।

अध्यक्ष कालूराज मेहता ने भी जिले में आयोजित कार्यक्रमों और आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

दत्तानी युद्ध स्थल पर हवन किया

रेवदर, (निसं)। रेवदर के समीपवर्ती दत्तानी गांव में स्थित दत्तानी युद्ध के महानायक ठाकुर समर सिंह देवडा पाडीव की स्मृति में बनी छतरी पर जीर्णोद्धार के बाद हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

चंद्रवीर सिंह लूणोल ने बताया कि 1583 ईस्वी में सिरोही महाराव सुरतान देवडा जिनका नेतृत्व समरा जी देवडा पाडीव कर रहे थे की सेना व मुगल शासक अकबर की सेना में यहां दत्तानी की धरती पर घनघोर युद्ध हुआ था जिसमें अकबर की सेना के सभी 149 कमांडर मारे गए थे और मुगल सेना की करारी हार हुई थी। इस युद्ध में सिरोही की सेना के सेनापति पाडीव ठाकुर समरा देवडा और कुम्भा मांडनौत देवडा सिलदर दोनों ने परम शूरवीरता और राष्ट भक्ति का परिचय दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त समर सिंह जी देवडा की छतरी जो कि दत्तानी गांव के मुख्य चौराहे पर बनी हुई है जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी का समाज बंधुओ ने आपसी सहयोग करके पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया हैं।

इस अवसर पर गणपत सिंह सेलवाडा, महेन्द्र सिंह मगरीवाडा, ईशवर सिंह सरण का खेडा, भवानी सिंह भटाणा, गुलाब सिंह मकावल, गणपत सिंह हमीरपुरा, चन्द्र वीर सिंह लुणोल, सोहन सिंह मकावल , अजीत सिंह निम्बोडा, सुल्तान सिंह डबाणी, रविन्द्र सिंह भटाणा, पूनम सिंह सोलकीं दत्ताणी, गोविन्द सिंह मारोल, दलपत सिंह थल, चन्द्रपाल सिंह मारोल, महावीर सिंह भटाणा, नरेंद्र सिंह मारोल सहित कई जने उपस्थित रहे।

महिला मोर्चा ने की सीवरेज व्यवस्था सुधारने की मांग

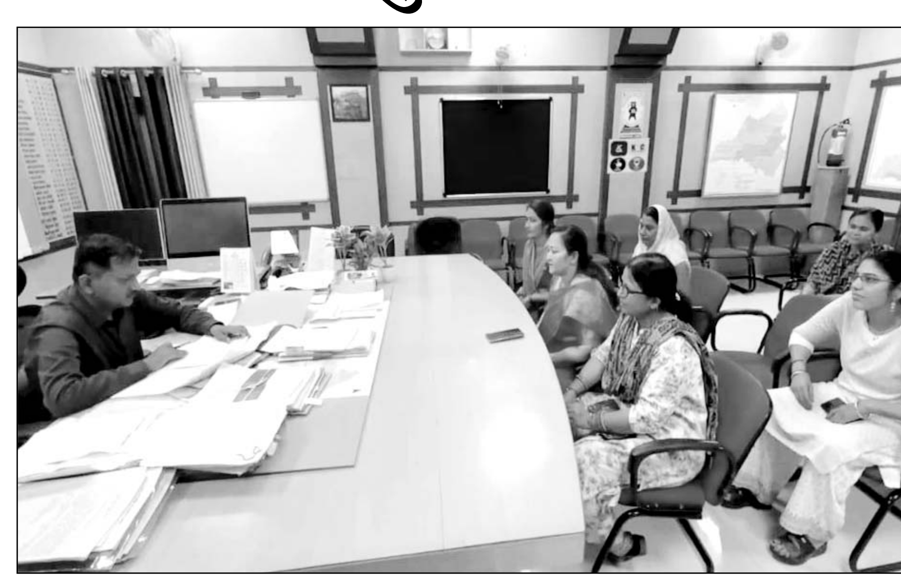

जालोर में सीवरेज से संबंधित समस्याओं को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मंजू सोलंकी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। शहर की सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से जाम होने के साथ घरो में रिटर्न हो रही गंदगी को दुरुस्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मंजू सोलंकी के नेतृत्व में जिला कलैक्टर जालोर डॉ.प्रदीप के .गावंडे को ज्ञापन सौपा गया।

ज्ञापन में बताया कि जालोर शहर के शिवाजी नगर सहित शहर में विभिन्न जगह सीवरेज समस्याओं से आमजन परेशान है। सीवरेज व्यवस्था सही नही होने से सिवरेज के पाईप ब्लॉक हो गये है तथा गंदा पानी रिटर्न घरो में आने से आमजन परेशान है सिवरेज पूरी तरह से जाम होने से उल्टी गंदगी रिटर्न होकर घरों में आ रही है। जिससे घरों के लोग बीमार हो रहे हैं। वही संक्रमण फैलने का खतरा महसूस हो रहा है और वायरल बुखार अमुमन इसी की वजह से हो गया है। सिवरेज की सुध लेने वाला कोई नही है। सिवरेज जाम से आमजन को दिक्कत का सामना करना पड रहा है, कहीं तो सिवरेज के यह हाल है कि ओवरफ्लो के कारण गंदगी सडकों पर फैल रही है, लेकिन प्रशासन व नगरपरिषद का ध्यान इस और नहीं जाने से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। गंदगी और दुग्ध का माहौल बन गया है। ज्ञापन में शिवाजी नगर सहित शहर भर में सीवरेज समस्या हल करने की मांग की गई।

ज्ञापन देने के दौरान मंजू सोलंकी, गायत्री गौड, सजु दवे, मीना सोलंकी, अन्जना, परमेश्वरी, शोभा, जया, पिंकी, प्रमिला, सजना आदि मौजूद रहे।

पाटोत्सव व राव धूहड़ जयंती आज

जोधपुर,(का.सं.)। मां नागणेचिया माता मंदिर नागाणा में शुक्रवार 4 अप्रैल को पाटोत्सव व राव धूहड़ जयंती का आयोजन किया जाएगा।

- प्रथम आरती के बाद मनोकामना पहाड़ की परिक्रमा होगी
- लाभार्थियों का बहुमान होगा

मां नागणेचिया माता मंदिर प्रबंधन समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह थोब ने बताया कि शुक्रवार को प्रातः 7:00 बजे मंदिर में प्रथम आरती के बाद मनोकामना पहाड़ की परिक्रमा होगी। उन्होंने बताया कि प्रातः 10:30 बजे राव धूहड़ जयंती का आयोजन होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गुड़ा मांगलिया के महेन्द्रा नन्द गिरी जी महाराज होंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राव धूहड़ जी व गुरु पीथड़ जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूजा के बाद मां नागणेचिया माता जी का पाटोत्सव मनाया जाएगा व ट्रस्ट की आम सभा आयोजित होगी और प्रगति विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह की प्रसादी का आयोजन जागसा के लाभार्थी राम सिंह , भगवान सिंह , खुमान सिंह, सवाई सिंह, नरपत सिंह व अखे सिंह की ओर से किया जाएगा व शाम की प्रसादी का आयोजन पोपटलाल , करनाराम सुथार शेरपुरा डीसा की ओर से होगा। लाभार्थियों का बहुमान भी होगा।

पाली में भारतीय नव वर्ष पंचांग का विमोचन हुआ

पाली ,(नि.सं.)। पाली में विद्या भारती सरस्वती शिक्षा समिति की ओर से संचालित सरस्वती विद्या मंदिर में भारतीय नव वर्ष पंचांग 2082 का विमोचन किया गया।

उत्सव प्रभारी नितेश तोषावरा ने बताया कि इस वर्ष संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष मै संघ की योजना के तहत पांच प्रमुख विषयों पर कार्य किया जाएगा। इनमें सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, स्व जागरण और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। हमारे भारतवर्ष में इसी पंचांग को लेकर इस सृष्टि का चक्र चलता है।

हमारे घर में शादी मुहूर्त गृह प्रवेश जन्मपत्री भारतीय पंचांग के आधार पर मनाए जाते हैं।

भैया को सम्बोधित करते हुए मुकेश कुमार राखेचा ने कहा की विद्या भारती की योजना अनुसार इसको प्रत्येक घर-घर तक पहुंचाया जाता है। जबकि अंठोजी पंचांग अंठोजों की ओर से स्थापित किया हुआ है।

यह पंचांग केवल तिथियों काविवरण नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का जीवंत चित्र है। इसमें सनातन धर्म के त्योहारों, विशेष अवसरों और दैनिक तिथियों की सटीक जानकारी दी गई है। पंचांग में चैत्र मास से लेकर सभी मासों का सरल वर्णन किया गया है।

इसमें आगामी सत्र के सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी शामिल है। पंचांग में पंच परिवर्तन के माध्यम से परिवार जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्यों के महत्व को दर्शाया गया।

इस अवसर पर प्रधानचार्य कृष्ण कुमार राजपुरोहित सुरेश कुमार पारस प्रजापति विश्वजीत सिंह मनीष कुमार पुनाराम अशोक चौधरी सूर्यप्रकाश श्रवण हर्षिता रौनक आदि उपस्थित रहे।

सुंधा माता पहाड़ी के रोप-वे पर मॉक ड्रिल सफल

जालोर के पास सुंधा माता पहाड़ी रोप-वे पर आपातकालीन स्थिति होने पर किये जाने वाले बचाव कार्यों के मॉक ड्रिल का सफल प्रदर्शन किया। फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। जालोर के पास जसवंतपुरा क्षेत्र में सुंधा माता पहाड़ी रोप-वे पर आपातकालीन स्थिति होने पर किये जाने वाले बचाव कार्यों के मॉक ड्रिल का सफल प्रदर्शन किया।

जसवंतपुरा के सुंधा पर्वत स्थित सुंधा माता मंदिर रोप-वे अटकने से 4 यात्रियों के फंसने की सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव, अतिरिक्त जिला कलैक्टर दौलतराम चौधरी, एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट विक्रम चौधरी, जसवंतपुरा उपखण्ड अधिकारी रामलाल मीणा, उप पुलिस अधीक्षक भवानीसिंह इंदा, बीसीएमओ डॉ. प्रशान्त सेन, जसवंतपुरा थानाधिकारी गुमानसिंह व ट्रस्ट के व्यवस्थापक जितेन्द्र सिंह, रोप-वे प्रबंधक प्रहलाद राय अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीम व मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंच कर रोप-वे बंद करवाया तथा आपातकालीन स्थिति होने पर किये जाने वाले बचाव कार्यो के मॉक ड्रिल का सफल प्रदर्शन किया। टीमों ने अपने साथ लाये गये बचाव संबंधित उपकरणों एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के तरीकों से रोप-वे पर आपातकाल में फंसे लोगों को बचाने का सफल प्रदर्शन किया । जिसमें लोगों का रोप-वे एवेकुशन व घायल लोगों का मौके पर चिकित्सा उपचार देकर स्टेबल किया गया तथा फंसे लोगों को शीट रेप्लिंग, रस्सी व सीट हारनेस के माध्यम से निकाला गया। जरूरतमंद व्यक्ति को सीपीआर देने व अग्निशमन यंत्रों के समुचित इस्तेमाल को लेकर एनडीआरएफ टीम द्वारा डेमोस्ट्रेशन दिया गया।

इस दौरान ट्रस्ट सदस्य, पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड टीम उपस्थित रही।

श्रीराम जन्मोत्सव पर चर्चा आज

जालोर, (कासं)। सनातन महोत्सव समिति जालोर की ओर से श्रीराम जन्मोत्सव शोभायात्रा को लेकर बैठक शुक्रवार को शाम 8.30 बजे जलंधरनाथ धर्मशाला जालोर में होगी।

सनातन महोत्सव समिति के संयोजक अम्बालाल व्यास ने यह जानकारी दी।

तहसीलदार का सम्मान किया

रेवदर, (निसं)। मण्डार में भील समाज ने आसुराम नायक का नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पर पदोन्नति होने पर शबरी एकलव्य विकास संस्थान कार्यालय पर स्वागत कार्यक्रम रखा। तहसीलदार को स्वागत के साथ संस्थान का दुपट्टा पहनाकर एकलव्य की तस्वीर भेंट की गई।

इस दौरान रतन राणा अमरापुरा ने समाज को सम्बोधित करते हुए शिक्षा के साथ साथ एकता बनाए रखने और राजनीतिक में समाज की भुमिका सम्बन्धित विस्तृत जानकारी बताई गई।

इस दौरान बाबुराम मानपुर, मफाराम मणडार, शैलेश कुमार निमबज,भरत कुमार आवलिया, अर्जुन राम, नारायण लाल,हाजरा राम, सोमतीराम, बाबुलाल, प्रताप राम, कालाराम, पोपटलाल, महेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार, शंकर लाल, ईश्वर रामजी, रमेश कुमार,हकिया राम, राणाराम, सोनाराम, नेनाकमारी, नीरु कुमारी सहित कई लोगों ने स्वागत किया।

गिव-अप अभियान में नाम नहीं हटाने पर 165 नोटिस

जालोर, (कासं)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों से नाम पृथक करवाने के लिए 30 अप्रेल तक 'गिव-अप अभियान' चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में अब तक 165 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले में अब तक 4792 परिवारों एवं 15577 सदस्यों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन किए हैं तथा 1203 परिवारों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट से आवेदन किए। विभागीय निर्देशानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी-अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीवकोपार्जन में प्रयुक्त हो), जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक की निर्धारित सीमा से अधिक हो, ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश के लिए निर्मित पक्का मकान हो, नगर परिषद क्षेत्र में 1 हजार वर्ग फीट व नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/ व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते है। योजना से नाम हटाने के लिए 30 अप्रेल, तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा अथवा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ का त्याग कर सकते है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य है और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे है। जो व्यक्ति 30 अप्रेल, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डॉ.पवन ओझा युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने

डॉ. पवन ओझा

जालोर, (कासं)। राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रामानुज शर्मा ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए डॉ. पवन ओझा को राजस्थान ब्राह्मण महासभा के युवा प्रकोष्ठ जालोर का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया।

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ओझा ने बताया कि वह अतिशीघ्र कार्यकारिणी का गठन कर ब्राह्मण समाज के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए महासभा के विधान, नियम एवं दिशा-निर्देशानुसार कार्य करेंगे। डॉ. ओझा के मनोनयन पर खुशी अभिव्यक्त की गई।

गौरतलब हैं कि इससे पूर्व भी डॉ.ओझा विप्र समाज के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए समाज के हितों में नियमित रूप से सक्रिय है।

कार्यालय ग्राम पंचायत लेटा पंचायत समिति, जालोर

क्रमांक/ग्रांप/मनरेगा /2025-26 /04 दिनांक: 03/04/2025

ई-निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

पंचायत समिति जालोर के अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेटा के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 शेष की अवधि के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओ में कराये जाने वाले कार्यो के लिए निर्माण स्रामगी एवं उपकरणो की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (आदिनांक संशोधित) के अनुसार राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत वस्तु एवं सेवाकर (GST) अधिनियम 2017 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकत अनुभवी एंव इच्छुक विर्निमाता (ओ) / विक्रेता (ओ) / फर्मो /संवेदको / आपूर्तिकताओ से जो किसी भी राजकीय संस्थान / उपक्रमों से बोली लगाने से विवर्जित /ब्लेक लिस्टेड नही हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से निविदाएं आमंत्रित की जाती है ई-निविदा संबधी समस्त विस्तत विवरण कार्यालय नोटिस बोर्ड तथा www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जाकर डाउनलोड कर www.eproc.rajasthan.gov.in. ई-निविदा ऑनलाईन अपलोड की जा सकती है ।

NIB No. - ZJR2526A0021
UBN No. - ZJR2526GLOB00023

सरपंच/ प्रशासक
ग्राम पंचायत,लेटा
पंचायत समिति जालोर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, लेटा
पंचायत समिति जालोर

राजस्थान लोक सेवा आयोग में रिक्त व नए पदों पर भर्ती की मांग

अधिकारी व कर्मचारी दो दिन की पेन डाउन हड़ताल पर, सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग में रिक्त व नए पदों पर कार्मिक की मांग को लेकर आयोग के कर्मचारी व अधिकारी दो दिवसीय पेन डाउन हड़ताल पर चले गए। गुरुवार से शुरू हुई पेन डाउन हड़ताल पर गए कार्मिकों ने कहा कि यदि उनकी मांग पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी व शासन प्रशासन की होगी। पेन डाउन हड़ताल के चलते आयोग में चल रहे इंटरव्यू, डीपीसी की बैठक, भर्ती संबंधित अभिस्तावन व रिजल्ट जारी करने सहित विभिन्न कार्य प्रभावित होंगे।

आरपीएसपी कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल के चलते प्रदर्शन किया।

आरपीएससी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिवाकर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि आयोग में 98 नए व रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कार्मिकों द्वारा गुरुवार से दो दिवसीय पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। इससे आयोग में चल रही विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल के कारण इंटरव्यू, डीपीसी की बैठक, भर्ती संबंधी अभिस्तावन और रिजल्ट जारी करने सहित अन्य प्रशासनिक कार्य बाधित हो गए हैं। कार्मिक 27 मार्च से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने सोमवार से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है।

आयोग के कार्मिकों पर पड़ा काम का अतिरिक्त भार :-समिति के अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि आयोग में वर्ष 2025 में 80 दिन के भीतर 158 परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। इन परीक्षाओं में 38 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। शर्मा का कहना है कि विगत वर्षों में करीब 15 से 18 लाख पंजीकृत अभ्यर्थियों की विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करवाई। स्टाफ की कमी के चलते कार्मिकों ने भारी दबाव के बीच काम किया, लेकिन इस वर्ष आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या लगभग दुगुनी हो चुकी है।

आयोग ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखे, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। जिसके चलते कर्मचारियों की संख्या कम होने से कार्यभार बढ़ गया है।

सामूहिक अवकाश की चेतावनी :-समिति के पदाधिकारियों व प्रदर्शनकारी कार्मिकों का कहना रहा कि आयोग प्रशासन से कई बार पदों में वृद्धि की मांग की गई, लेकिन आज तक सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है, उन्होंने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार ने जल्द ही नई भर्ती के आदेश जारी नहीं किए तो कर्मचारी और अधिकारी सामूहिक अवकाश पर

■ **पेन डाउन हड़ताल से आयोग में चल रही विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं**

चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि आयोग में इन दिनों राजनीतिक विज्ञान के साक्षात्कार कर चल रहे हैं, जिन्हें हड़ताल से दूर रखा गया है जो कार्मिक साक्षात्कार प्रक्रिया से जुड़े हैं, वे काम कर रहे हैं।

प्रभावित होंगी परीक्षाएं :- प्रदर्शनकारी कार्मिकों का कहना रहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे जिसके चलते आयोग में आगाम माह में होने वाली सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा परीक्षा 2023 के राजनीतिक विज्ञान के इंटरव्यू 24 मार्च से 9 अप्रैल तक चल रहे हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के इंटरव्यू 21 अप्रैल से शुरू होंगे। कृषि अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 20 अप्रैल को होना है, जिसमें 52 पदों के लिए परीक्षा प्रभावित होगी।

हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस टीम ने जयपुर पहुंचकर मुल्जिम के संभावित स्थानों पर दबीश देकर पकड़ा

खेतड़ी, (निसं)। पचेरी कलां पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि 11 मार्च 2024 को बिजारणियां की ढाणी तन गुढ़ागौड़जी निवासी संजय ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई राजेश कुमार पुत्र सरदारा राम 10 मार्च को सुबह करीब दस बजे पर घर से निकला था। इसके बाद पचेरी थाना

■ **आरोपी पर पुलिस ने 10 हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा था**

से घर पर फोन आया तब पता चला कि उसका भाई राजेश कुमार मृत अवस्था में बावरिया बस्ती पचेरी गढ़ के पास मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसके साथ पर्वतसिह पुत्र रघुनाथ निवासी टिटनवाड, दयानन्द पुत्र प्रभातीलाल निवासी टिटनवाड, सुमेरसिंह पुत्र मातुराम मेघवाल सहड़ का बास थे। इसकी हत्या करके इनको बावरिया बस्ती पचेरी गढ़ के पास छोड़ गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर नामजद आरोपी दयानन्द को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया तथा दस हजार रुपए के इनामी वांछित आरोपी पर्वतसिंह की तलाश के लिए टीम गठित कर तेलंगाना हैदराबाद को रवाना किया गया। इस दौरान आरोपी पर्वतसिह का जयपुर में होने की सूचना मिली। जिस पर पुलिस टीम ने जयपुर पहुंचकर मुल्जिम के संभावित स्थानों पर दबीश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान टीम में थानाधिकारी राजपाल सिंह, एचसी वीरेंद्र, कांस्टेबल रामसिंह, कमलेश आदि शामिल थे।

पचेरी कलां पुलिस ने हत्या के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया।

पति की मौत के 14 साल बाद पत्नी ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया

सात परिचितों के साथ झारखंड गए थे, वहीं जहर देकर मार डालने का आरोप

पाली, (निसं.)। 14 साल पहले 2010 में एक युवक अपने सात दोस्तों के साथ धार्मिक यात्रा पर पाली से झारखंड गया। उसके दोस्तों ने लौटकर युवक की पत्नी को बताया कि वे कहां चले गए, पता नहीं। इस घटना के 14 साल बाद 2024 में पति की तलाश में महिला खुद झारखंड गई और पति के बारे में पता लगाना शुरू किया। जानकारी मिली कि पति होटल में मृत पाया गया था। अब महिला ने पाली के औद्योगिक नगर थाना में पति के सात दोस्तों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कराया है।

औद्योगिक नगर थाने के जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पाली के पुराना हाउसिंग बोर्ड इलाके में रहने वाली मधु देवी (52) ने पति संपत राम की मौत के 14 साल बाद सात लोगों के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज

■ **पत्नी ने पति के सात दोस्तों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कराया है**

कराया है। रिपोर्ट में मधु देवी ने आरोपियों पर पति को जहर देकर मारने के आरोप लगाए हैं।

रिपोर्ट में मधु देवी ने बताया कि साल 2010 में मेरे पति संपत राम नवरात्र के दिनों में अपने 7 दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकले थे। घर पर यह कहकर गए थे कि 4-5 दिन में लौट आएंगे। कुछ दिन बाद उनके दोस्त लौट आए लेकिन पति नहीं लौटे। उनके दोस्तों से पूछा तो वे बोले कि सभी झारखंड के धनबाद गए थे, संपत हमसे पहले ही वहां से निकल गए थे, वे कहां चले गए पता नहीं। मेरा बेटा उस वक्त काफी छोटा था। परिवार में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए पति का पता नहीं लगा पाई। पाली में रह रहे लोगों के घर जाकर उनसे पूछती थी लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पति के साथ आखिर क्या हुआ? वे जिंदा हैं या मर गए? यह जानने के लिए मैं 3 सितम्बर 2024 को जोधपुर से ट्रेन में बैठकर झारखंड के धनबाद गई। वहां रेलवे स्टेशन पर रुकी। फिर नजदीकी थाने में पति की फोटो दिखाकर 14 साल पहले की बात बताई।

धनबाद पुलिस ने बताया कि संपतराम की बॉडी धनबाद के एक होटल में 30 मार्च 2010 को मिली थी। पोस्टमॉर्टम में सामने आया कि उसकी मौत जहर से मौत हुई थी। उसके परिचितों ने बॉडी ली थी और अंतिम संस्कार भी कर दिया थी। महिला ने धनबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही लेकिन कहा गया कि रिपोर्ट पाली में ही दर्ज करानी होगी। मधु देवी ने बताया कि पाली में एसपी ऑफिस से लेकर थाने में कई चक्कर काटे। लेकिन सबूतों के अभाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट के जरिए पाली के औद्योगिक नगर थाने में 7 जनों के खिलाफ पति को लेकर जाने और जहर देकर मारने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। महिला ने औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के चिमनपुरा गांव में रहने वाली कांतादेवी, लक्ष्मण, मीना, भगवती उर्फ बबली उर्फ हंजा, पाली के टैगोर नगर निवासी श्याम, धनबाग झारखंड निवासी मनोज कुमार, धनबाद निवासी राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि घूमने ले जाने के बहाने इन लोगों ने पति को जहर देकर मार डाला।

सहकारिता मंत्री ने बैठक ली

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना खरीद के दृष्टिगत पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रक्रिया 10 अप्रेल से पहले सम्पन्न करने के प्रयास किए जाएं। दक गुरुवार को अपेक्स बैंक में इस सम्बन्ध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार बाजार भाव की तुलना में समर्थन मूल्य आकर्षक होने की वजह से खरीद केन्द्रों पर सरसों एवं चना की अधिक आवक होने की संभावना है। राज्य सरकार भी खरीद के लक्ष्य पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: इसे ध्यान में रखते हुए खरीदी गई उपज के भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो प्राइवेट गोदाम किराए पर लिए जाएं। साथ ही, तिलम संघ एवं बीज निगम के गोदाम भी उपलब्ध करवाने पर विचार किया जाए।

हिंदुस्तान स्काउट छात्रों ने ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभाई

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के तहत जी स्कूल में संचालित हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स ने भीलवाड़ा के आम नागरिकों से ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाइश करते हुए नियमों की पालना करने के लिए आग्रह किया। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने स्काउट बालकों को नियमों के बारे में जानकारी दी।

भीलवाड़ा शहर के विभिन्न चौराहो पर स्काउट के बालकों ने ट्रैफिक खुलवाया और नियमों के बारे में आम जनता को नियमों की पालना करने के लिए आग्रह किया। वहीं सबसे व्यस्ततम अजमेर चौराहा पर जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए, उनके चालान भी बनवाए। पुलिस कर्मियों ने बालकों को कम आयु वर्ग के बालकों के लिए कौन सा वाहन चलाना चाहिए और कौन सा नहीं इसके बारे में जानकारी दी, वहीं हमें सड़क पर चलते समय किन नियमों की पालना करनी चाहिए इसके बारे में भी स्काउट बालकों को समझाया। ट्रैफिक पुलिस केस मीन से बालकों में और आने वाली नव युवा पीढ़ी में सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। हिंदुस्तान स्काउट छात्रों ने पुलिस की भूमिका को निभाते हुए यातायात खुलवाया और जिन नियमों के अनुसार चालान बनना चाहिए उन लोगों का चालान भी कटवाया। हिंदुस्तान स्काउट मास्टर पवन बावरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जी स्कूल में संचालित हिंदुस्तान स्काउट छात्रों द्वारा पुलिस कर्मियों की इस मुहिम से कुछ दिखाई दिए और इस दौरान शपथ भी ली कि हम ट्रैफिक नियमों की पालना करेंगे और आने वाले समय में हम लोगों को और हमारे परिवार जनों को जागरूक करेंगे, जिससे भीलवाड़ा शहर ही नहीं पूरे जिलेभर में किसी प्रकार से कोई सड़क हादसे के शिकार ना हो और गाड़ी चलाते समय सुरक्षित रहकर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।

पुलिस कर्मियों ने छात्रों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी।

गायब मोबाइल ढूंढ़ निकालेगा रेलवे सुरक्षा बल

जयपुर। रेल यात्रियों के गुमशुदा या गायब मोबाइल फोन को ढूंढ निकालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दूरसंचार विभाग से हाथ मिलाया है। इसके तहत आरपीएफ ने दूरसंचार विभाग के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल के साथ सफल साझेदारी की है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) में एक पायलट प्रोग्राम की सफलता के बाद यह पहल की गई है। भारतीय रेल द्वारा इस पहल को पूरे भारत में लागू किए जाने के बाद करोड़ों रेल यात्रियों को फायदा मिलेगा।अपना गुम मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए यात्री इसकी रिपोर्टिंग रेल मदद या 139 डायल के जरिए कर सकते हैं। यदि यात्री एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते, तो उन्हें सीईआईआर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराने का भी विकल्प मिलेगा।

यात्रियों की सुविधा के लिए कैलादेवी मंदिर परिसर का निरीक्षण किया

मंदिर के सोल ट्रस्टी के पुत्र युवराज विवशवत पाल ने निरीक्षण कर निर्देश दिए

करौली, (निसं)। आने वाली दुर्गा अष्टमी पर कैलादेवी मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर के सोल ट्रस्टी के पुत्र युवराज विवशवत पाल ने यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर का निरीक्षण कर ट्रस्ट प्रबंधन को विशेष दिशा निर्देश दिए।

इन दिनों उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ तीर्थ स्थल आस्था धाम कैलादेवी में चल रहे मेले के दौरान शुक्रवार सप्तमी और शनिवार को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट के सोल ट्रस्टी कृष्णचंद्र पाल के पुत्र विवशवत पाल गुरुवार को प्रात: कैलादेवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी के दर्शन कर क्षेत्र में अमन चैन और खुशहाली की मनौती मांगी। इसके पश्चात मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, प्रबंधक प्रशासन चन्द्रकांत कुडतकर, प्रबंधक स्थापना प्रदीप द्विवेदी, कार्यकारी अधिकारी किशन पाल सिंह जादौन, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कैप्टन कल्याण सिंह, कैलादेवी मेला मंदिर कंट्रोल रूम प्रभारी एडवोकेट संतोष सिंह, मुख्य परिचालन अधिकारी मंदिर ट्रस्ट विवेक द्विवेदी के साथ मंदिर चौक में पहुंचे, जहां रेलिंग में लग रहे दर्शनार्थियों से व्यवस्था सुधार में और क्या किया जाए को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को सप्तमी और शनिवार को पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी की भीड़ को देखते हुए पूरी रेलिंग में पीने के पानी की जगह-जगह बोतलें रखवाकर निशुल्क वितरण करवाने, दोपहर के समय गर्मी के मौसम को देखते हुए हवा के लिए पंखे और कूलर लगवाने के अलावा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कैलादेवी मंदिर में मेले के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे स्काउट गाइड के बालकों से चर्चा करते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाये और किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

ऊर्जा राज्यमंत्री ने बाबा श्याम के दर्शन किए

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का श्याम दुपट्टा ओढाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया।

सीकर, (निसं)। ऊर्जा विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर गुरूवार को खाटूश्यामजी पहुंचे और उन्होंने खाटूश्यामजी मंदिर में पूजा-दर्शन किए। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने विधिवत रूप से पूजा-अर्चना करवाई तथा श्याम दुपट्टा ओढाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया।

ऊर्जा राज्यमंत्री नागर ने श्याम मंदिर में दर्शन के बाद जिले के अधिकारियों से विभागीय चर्चा कर खाटूश्यामजी में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि आज से यहां अण्डरग्राउण्ड लाईन के काम का भी शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाटूश्यामजी क्षेत्र में नया जीएसएस बनाया है जिससे यहां की विद्युत तंत्र की आपूर्ति को सुदृढ़ होगी। जीएसएस के बनने से यहां के निवासियों को और अधिक विद्युत आपूर्ति की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि यहां आने वाले खाटू भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए ऊर्जा विभाग लगातार प्रयासरत है तथा जो भी यहां के सुझाव होंगे उन्हें राज्य सरकार को भेजकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जायेगा। इस दौरान अधीक्षण अभियन्ता विद्युत अरूण जोशी, डीवाईएसपी रींगस संजय बोथरा, थानाधिकारी पवन कुमार चौबे, मंदिर कमेटी के सदस्य प्रताप सिंह चौहान, विद्युत विभाग के अधिकारी-कार्मिक मौजूद रहे।

दो गिरफ्तार

जयपुर। प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से अधिक मोबाइल स्नेचिंग की वारदात करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 17 एंड्रॉयड मोबाइल फोन सहित वारदात में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन भी जब्त किया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वनी गौतम ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल स्नेचिंग की वारदात करने वाले बलराम उर्फ बन्टु निवासी सेवर जिला भरतपुर हाल मुरलीपुरा जयपुर और जनक गुर्जर निवासी भुसावर जिला भरतपुर हाल रेनवाल जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में प्रताप नगर, सांगानेर, सीतापुरा और जगतपुरा इलाकों को दो दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा किया है और उनके पास से 17 एंड्रॉयड मोबाइल फोन सहित एक दुपहिया वाहन बरामद किया है। आरोपित बलराम और जनक पूर्व में चालानशुदा है और आदतन अपराधी है। दोनो ही टैक्सी गाडी चलाते है। टैक्सी गाड़ी को खड़ी करके स्कूटी और चोरी की बाइक से मोबाइल स्नेचिंग की वारदात करते है। आरोपी प्रताप नगर थाना इलाके में स्नेचिंग करते रहते है और दूसरे थाना क्षेत्र रहते है।

चोरी के शक में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई

कोटा, (निसं)। कुन्हाडी इलाके में मंदिर में चोरी के शक में पेड़ से बांधकर मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्यवाही करते हुए व्यक्ति को मुक्त कराया और मानसिक रूप से विमंदित व्यक्ति को अपना घर संस्था में भिजवाया गया। बाद मे पुलिस टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि गुरूवार को कुन्हाडी थाने में सूचना मिली कि इलाके के लैंडमार्क सिटी में एक व्यक्ति को चोर समझकर पेड से बांध रखा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मौके पर काफी भीड़ जमा थी और एक व्यक्ति को पकड़ रखा था। शहर एसपी ने बताया कि लोगों ने पुलिस को

■ **पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को मुक्त कराया**

■ **मानसिक रूप से विमंदित व्यक्ति को अपना घर संस्था में भिजवाया**

बताया कि व्यक्ति ने मंदिर के सामान को बाहर फेंक दिया जो मंदिर के समीप नहर पर पड़े हुए थे। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर उक्त व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम धन्नाराम (46) निवासी झांसी बताया लेकिन मंदिर आने का कारण पूछा तो वह कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति मानसिक रोगी प्रतीत हुआ उसे टीम थाने ले आई और उक्त व्यक्ति को अपना घर संस्थान में दाखिल कराया। उक्त व्यक्ति के परिजनों की तलाश की जा रही है। वहीं मंदिर के पुजारी ने लिखित रिपोर्ट दी थी कि एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति मंदिर में घुस गया। वहां रखे कपड़े उठाकर इधर-उधर फैला दिये व मंदिर के सामान को भी अस्त-व्यस्त कर दिया। उक्त व्यक्ति द्वारा जो सामान फैलाया गया था वह पूरा मिल गया। मंदिर में किसी प्रकार की चोरी नही हुई है। शहर एसपी ने बताया कि इसी घटनाक्रम के संबध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उक्त व्यक्ति पेड़ से बंधा हुआ था और उससे कुछ जने मारपीट कर रहे थे। वायरल वीडियो की पड़ताल कर पहचान के आधार पर बड़ोद निवासी रवि मेघवाल को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। वही बंधक से मारपीट करने वाले दो अन्य के बारे में पूछताछ जारी है।

बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। बपावर पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों के पास से अलग-अलग स्थानों से चोरी की गई पांच मोटरसाइकिलें भी बरामद की है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि एक अप्रेल को फरियादी देशराज ने बपावर कलां थाने पर रिपोर्ट दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि बेलदारी का काम करता है। 29 मार्च को खेत पर मोटरसाइकिल लेकर गया था मोटरसाइकिल को रोड के किनारे खड़ी कर खेत में रखवाली कर रहा था, कुछ समय बाद खेत से वापस आया तो उसको उसकी मोटरसाइकिल मौके पर नही मिली। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि मौके पर विनोद लक्ष्कार, रोहित माली और कल्लू कुशवाह घुमते हुए नजर आये। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसे संदेह है कि तीनों ही उसकी मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गये। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान करते हुए पुलिस व साइबर टीम द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण किया गया।

कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिली कि दो जने बपावर कलां व मोईकलां क्षेत्र में चोरी की वारदात करने की फिराक में घूम रहे है। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि मुखबीर की सूचना

चोरी की मोटरसाइकिल सहित चार जनों को गिरफ्तार किया।

■ **चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद की**

पर उपनिरीक्षक थानाधिकारी अभय सिंह व साईबर टीम के सहायक उपनिरिक्षक भुपेन्द्र हाडा के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर रवाना की गई। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि टीम ने कार्यवाही करते हुए बपावर कलां निवासी विनोद लक्षकार (20) एवं सचिन नागर (21) को गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि पकड़े गये दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद 3 अलग-अलग स्थानो से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलों को भी बरामद की गई। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश करने में गठित टीम के हैड कांस्टेबल रामानन्द और कांस्टेबल शंम्भुसिंह की अहम भूमिका रही है।

खेल जगत

मेरी टीम जल्द ही अपना सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हासिल करने में सक्षम है और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब के लिए चुनौती पेश कर सकती है। - चार्लोट एडवर्ड्स

इंग्लैंड की नवनियुक्त कोच, अपनी टीम के बारे में बोलते हुए।

आज का खिलाड़ी

कीरोन पोलार्ड

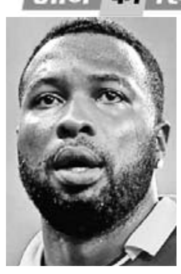

इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में खराब फार्म से जूझ रहे भारतीय ओपनर रोहित शर्मा का बचाव करते हुये मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड ने गुरुवार को कहा कि कुछ मैचों के आधार पर दिग्गज बल्लेबाज की फार्म का आकलन करना सही नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ शुक्रवार को खेले जाने वाले मैच की पूर्व संध्या पर एक प्रेस कांफ्रेंस में पोलार्ड ने कहा रोहित क्रिकेट के लीजेंड हैं। उनके नाम रिकार्ड बुक में कई रिकार्ड दर्ज हैं। कुछ मैचों के आधार पर उनकी बल्लेबाजी को आंकना सही नहीं होगा। उनका बल्ला कभी भी आग उगल सकता है।

क्या आप जानते हैं ?... अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का गठन 1946 में हुआ था और 2016 तक 197 सदस्य महासंघ हैं। यह खेल यूरोप में सबसे लोकप्रिय है।

केकेआर ने एकतरफा मुकाबले में सनराइजर्स को 80 रन से हराया

कोलकाता, 3 अप्रैल। आजिक्य रहाणे (38),अंगकृष रघुवंशी (50), वेकटेश अय्यर (60) और रिंकू सिंह (32 नाबाद) की बेहतरीन पारियों के बाद वैभव अरोड़ा (29 रन पर तीन विकेट) और वरुण चक्रवर्ती (22 रन पर तीन विकेट) के कातिलाना प्रदर्शन की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें मुकाबले में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 80 रन से एक तरफा जीत दर्ज की।

ईडन गार्डन मैदान पर कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुये पांच विकेट पर 200 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया और बाद में हैदराबाद की पारी को 16.4 ओवर के खेल में 80 रन पर समेट दिया। कोलकाता ने आज खेल के हर विभाग में हैदराबाद को बौना साबित कर दिया। हैदराबाद की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज हाइनरिक क्लासन (33) ने कुछ दर्शनीय शाट खेलकर दर्शकों का मनोरजंन किया मगर यह उनकी टीम को करारी हार से बचाने के लिये नाकाफी था। क्लासेन के अलावा कामिंडु मेंडिस (27), नीतिश कुमार रेड्डी (19) और कप्तान पैट कमिंस (14) ही अपने निजी स्कोर को दहाई तक पहुंचा सके।

इस हार के साथ हैदराबाद की प्लेआफ की दौड़ पर बने रहने की चुनौती और कड़ी हो गयी है। ईडन गार्डन मैदान पर क्विटन डी कॉक (1) और सुनील नारायण (7) के विकेट तीसरे ओवर के बीच में ही उखड़ चुके थे और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 16 रन टंगे थे।

फुटबॉल कोचिंग कोर्स सम्पन्न

जयपुर, 3 अप्रैल। अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ से मान्यता प्राप्त फुटबॉल कोचिंग कोर्स "डी लाइसेंस" सफलतापूर्वक जयपुर में संपन्न हुआ। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि

यह छह दिवसीय फुटबॉल कोचिंग कोर्स 28 मार्च से 2 अप्रैल के मध्य रॉयल फुटबॉल क्लब जयपुर में आयोजित किया गया। इस कोर्स को कराने हेतु अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ के मान्यता प्राप्त कोर्स इंस्ट्रक्टर सैयद अल्ताफउद्दीन अहमद आए। इस कोर्स में राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थान से आए 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें तीन महिला कोच शामिल है। दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से राजस्थान फुटबॉल संघ को और नए फुटबॉल कोच मिलेंगे जो कि इस राज्य में और बेहतर खिलाड़ियों को ग्रासरूट लेवल से तैयार करने में योगदान देंगे।

महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर के लिए अंपायर, मैच अधिकारी घोषित

दुबई, 3 अप्रैल। इस महीने होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर के लिए अंपायर और मैच अधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। छह टीमों का यह टूर्नामेंट नौ से 19 अप्रैल के बीच पाकिस्तान में होगा, जिसमें दो शीर्ष टीमें इस साल के आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में अपनी जगह पक्की करेंगी। पैनल में 10 अंपायर और तीन मैच रेफरी शामिल होंगे, जबकि मेजबान देश पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व फैजल खान अफरीदी और सलीमा इम्तियाज अंपायरिंग पैनल में करेंगे। पिछले साल सलीमा आईसीसी अंपायरों के पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनीं थीं। उन्होंने उस समय कहा था कि वह एशियाई देश के अंपायरों की नई पीढ़ी को प्रेरित करेंगी।

आईसीसी मीडिया स्टेटमेंट के अनुसार, बांग्लादेश के पैनल में मसुदुर रहमान मुकुल और शतीरा जाकिर जेसी के रूप में दो अंपायर भी हैं, जबकि जिम्बाब्वे की सारा दंबनेवाना के साथ डोनोवन कोच, बैब्स गकुमा, कैंडेस ला बोर्डे, डेडुनु डी सिल्वा और शॉन हैग भी शामिल हैं। अली नकवी, शैंड्रे फ्रिट्ज़ और ट्रूडी एंडरसन मैच रेफरी के रूप में मौजूद रहेंगे और आईसीसी के वरिष्ठ प्रबंधक अंपायर और रेफरी, सीन ईज़ी का मानना है कि यह टूर्नामेंट पूरे पैनल को अपनी साख दिखाने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा।

रेफरीः अली नकवी (पाकिस्तान), शैंड्रे फ्रिट्ज़ (दक्षिण अफ्रीका), ट्रूडी एंडरसन (न्यूजीलैंड)। **अंपायरः** बैब्स गकुमा (दक्षिण अफ्रीका), कैंडेस ला बोर्डे (वेस्ट इंडीज), डेडुनु डी सिल्वा (श्रीलंका), डोनोवन कोच (ऑस्ट्रेलिया), फैसल खान अफरीदी (पाकिस्तान), मसुदुर रहमान मुकुल (बांग्लादेश), सलीमा इम्तियाज (पाकिस्तान), सारा दंबनेवाना (जिम्बाब्वे), शतीरा जाकिर जेसी (बांग्लादेश), शॉन हैग (न्यूजीलैंड)।

अनुराग मिश्रा स्मृति बी डिवीजन लीग

जहीरुल हसन क्लब ने डायमंड क्लब को हराया

जयपुर, 3 अप्रैल। जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अनुराग मिश्रा स्मृति बी डिवीजन लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में खेले गए पूल ए के मैच में जहीरुल हसन क्लब ने डायमंड क्लब क्लब को 28 रनों से हराया। जी आर ग्राउंड पर खेले गए मैच में

जहीरुल हसन क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तुषार चेलानी के 63 रन, सियाराम चौधरी के 81 रन, आलोक गुर्जर के 49 रन, सूर्यांश के 22 रन से 48.4 ओवर में 289 रन बनाए। डायमंड क्लब के लिए संजय महावार ने 42 पर 6, देवांश सिंह ने 60पर 3 विकेट लिए। जवाबी पारी में डायमंड क्लब की टीम रफीक जोया के 57 रन, देवांश सिंह के 31 रन, कुमार वासु के 33 रन, रुद्र सोनी के 24 रन, वेदांग शर्मा के नाबाद 31 रन व अनस मंसूरी के नाबाद 19 रनों से 50 ओवर में 9 विकेट पर 261 रन ही बना सकी। जहीरुल हसन क्लब के लिए चंदन चौधरी ने 48 पर 2, गौरव पुनिया ने 42 पर 2, प्रतीक चौधरी ने 1 विकेट लिया। कल स्टार क्लब बनाम ज्योति बा फूले क्लब के मध्य मैच खेला जाएगा।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने आईपीएल आयोजन के लिए 11 सदस्य समिति का किया गठन

जयपुर, 3 अप्रैल। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लंबे समय से चल रही आयोजन समिति को लेकर असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है। गुरुवार को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने आयोजन के लिए समन्वय समिति की घोषणा कर दी। परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया को आयोजन समिति का संयोजक बनाया गया है, जबकि महावीर मीणा को सहसंयोजक नियुक्त किया गया है। कुल 11 सदस्यीय समिति के सदस्यों को आयोजन से जुड़ी अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दरअसल, जयपुर में 13 अप्रैल से शुरू होने जा रहे आईपीएल के आयोजन को सफल बनाने के लिए अब प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सुरक्षा से लेकर टिकट वितरण तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का मानना है कि इस बार जयपुर में होने वाले मुकाबलों को दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव बनाया जाएगा। इसके अलावा, सुरक्षा व्यवस्था, स्टेडियम प्रबंधन, अतिथि सत्कार, लॉजिस्टिक्स और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी समितियां गठित की गई हैं।

अनुभवी अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

आयोजन समिति में मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया और खेल प्रबंधन विशेषज्ञ रणविजय सिंह चंपावत को अहम भूमिकाएं दी गई हैं। रणविजय सिंह चंपावत को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया मैनेजमेंट की कमान मुख्य जनसंपर्क अधिकारी तेजराज सिंह को दी गई है। इसके साथ ही नरेंद्र भूरिया, कोमल चौधरी और अनिरुद्ध जगधारी को भी आयोजन से जुड़े विभिन्न कार्यों में शामिल किया गया है। जबकि सहायक अभियंता मनीष बाजिया, खेल अधिकारी करण सिंह, सहायक लेखा अधिकारी अनिल जैन, क्रिकेट प्रशिक्षक मनीष वर्मा और हैंडबॉल प्रशिक्षक अतुल शर्मा को आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया गया है। सभी सदस्यों को उनके अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, ताकि आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

कुल 11 समितियों का किया गया गठन

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने आयोजन से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए 11 अलग - अलग समितियों का गठन किया है। इन समितियों में संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों को शामिल किया गया है। पिच और ग्राउंड प्रबंधन समिति- कोमल चौधरी, मनीष वर्मा और साजिद खान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जबकि मीडिया मैनेजमेंट समिति- जनसंपर्क अधिकारी तेजराज सिंह को संयोजक और एम. कलीम को सहसंयोजक नियुक्त किया गया है। इसी तरह टिकट व्यवस्था समिति - नरेंद्र भूरिया, तेजराज सिंह और राजेश शर्मा को टिकट वितरण और व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।

के.एम. रूंगटा चैलेंजर ट्रॉफी

मनन सिंह शेखावत का शतक

जयपुर, 3 अप्रैल। जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित के एम रूंगटा चैलेंजर ट्रॉफी में जयपुरिया ग्राउंड पर खेले गए तीन दिवसीय मैच के दूसरे दिन डी एस जे टीम ने पहले दिन के स्कोर से आगे खेलते हुए मनन सिंह शेखावत के शतक 114 रन (217 गेंद, 17 चौके), हार्दिक कुक्कड़ 82 रन, राजवीर सिंह के 66 रन, तोषित भाटिया के 56 रन, हिमांशु राणा के 91 रन, कुणाल गौतम के नाबाद 36 रन से

129 ओवर में 7 विकेट पर 515 रन बनाए। एस के आई टी इलेवन के लिए निखिल कोहली ने 99 पर 4 विकेट लिए। संक्षिप्त स्कोर - एस के आई टी इलेवन - 48.5 ओवर 186 रन। डी एस जे इलेवन - 129 ओवर में 7 विकेट 515 रन। मनन सिंह शेखावत नाबाद 114 रन, हार्दिक कुक्कड़ 82 रन, कुणाल गौतम नाबाद 36 रन, हिमांशु राणा 91 रन। हर्षित शर्मा, आर्यन जैन व मोहित भगतानी ने 1 - 1 विकेट लिए। दूसरे मैच में के एल सैनी स्टेडियम पर आज से शुरू हुए मैच में आर एच सी एल एस एस टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राहुल खण्डेलवाल के 92 रन, विवेक सैनी के 69 रन, रोहन राजभर के 47 रन, शुभम शर्मा के 78 रन, शुभम सिंह के 47 रन, मिहित अग्रवाल के नाबाद 17 रन, हर्ष यादव के 45 रनों से पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 90 ओवर में 8 विकेट पर 453 रन बनाए। एम जे जे ग्रुप इलेवन के लिए प्रखर शर्मा ने 111 पर 2, अभिषेक यादव ने 82 पर 3, रोहन सिंह ने 62 पर 2 व आर्यमन कटारिया ने 13 पर एक विकेट लिया।

राजधानी

'संवैधानिक पद की मर्यादा का ध्यान रखें जूली, हवा में बात करने से हकीकत नहीं बदलती'

- पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया
- राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के लगभग 11,000 एमओयू हुए

जयपुर। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा राइजिंग राजस्थान को लेकर दिये गये बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि तराजू हाथ में लेकर खुद बेकसूर बन बैठे पर इतिहास उठाकर देख लो, कितने कसूर कर बैठे। टीकाराम जूली, मैं स्वयं नेता प्रतिपक्ष रहा हूं और मैंने इस पद की गरिमा और जिम्मेदारी को बखूबी समझा है लेकिन कांग्रेस की तरह विधानसभा में सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद कभी नहीं रहा। मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर कभी भी सामाजिक सम्मान जैसे दादी शब्द को लेकर सदन में गतिरोध उत्पन्न करने जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया था।

राठौड़ ने कहा कि "राइजिंग राजस्थान" को "लाइजिंग राजस्थान" बनाने के आपके आरोपों को मैंने पढ़ा। अच्छा रहता कि आप 35 लाख करोड़ के एमओयू में से किन-किन एमओयू में तथाकथित लाइजिंग हुई है उसका तर्कसंगत व सत्यता के साथ खुलासा करते। हवा में बातें उछालने से हकीकत नहीं बदलती। आप नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इस पद की मर्यादा का भी ध्यान रखें। आपने जमीन हथियाने का जो आरोप लगाया है तो आप यह खुलासा करें कि कितनी फर्जी कंपनियों ने जमीन हथिया ली? इसकी सूची जारी करें। महज आरोप लगाने से सच्चाई नहीं बदलती, हिम्मत है तो प्रमाण पेश करें।

राठौड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि यह 35 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से आ गया। मैं बताना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के 10 हजार 500 से अधिक एमओयू भजनलाल सरकार की कड़ी मेहनत का परिणाम हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन चार माह के अल्प समय में किया गया लेकिन फिर भी प्रयासों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नही छोड़ी गई।

पोषण पखवाड़ें में पहले स्थान पर लाने के लिए कार्य किया जाए : दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास डॉ. मंजू बाघमार तथा शासन सचिव महेन्द्र सोनी की उपस्थिति में गुरुवार को सचिवालय से वीसी के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस के अधिकारियों को प्राकृतिक रूप से अवसर मिला हुआ है कि वे आंगनबाड़ियों के बच्चों की पोषण सेवा करके स्वस्थ राज्य और राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 8 से 22 अप्रैल तक आयोजित हो रहे राजष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राष्टीय स्तर पर राज्य के पिछले साल के चौथे स्थान के प्रदर्शन में सुधार कर, पहले स्थान पर लाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए।

दिया कुमारी ने राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास डॉ. मंजू बाघमार तथा शासन सचिव महेन्द्र सोनी की उपस्थिति में गुरुवार को सचिवालय से वीसी के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त उपनिदेशकों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में उक्तानुसार आईसीडीएस अधिकारियों को आंगनबाड़ियों के बच्चों के लिए तत्परता और सेवाभाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आदर्श आंगनबाड़ियों के निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाए और साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में चल रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बेहतर प्रदर्शन कर राज्य को इस योजना में नम्बर एक राज्य बनाने का कार्य किया जाए।

लॉजिस्टिक्स हब बनने की ओर अग्रसर राजस्थान

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस महोत्सव में जारी की थी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025

जयपुर। राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी।

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहां लगने वाले उद्योग लॉजिस्टिक्स एवं परिचालन लागत को कम रखते हुए निर्यात के साथ-साथ स्थानीय मांग को भी बखूबी पूरा कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करते हुए, हमारा राज्य देश के लगभग 40 प्रतिशत बाजार तक पहुंच रखता है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है।

एकल पट्टा प्रकरण : पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र पर बहस रही अधूरी

जयपुर। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े एकल पट्टा प्रकरण में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। अदालत मामले में 7 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सीजे एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और शांति धारीवाल सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले अशोक पाठक को प्रकरण में पक्षकार बनाने को लेकर एकलपीठ में गुरुवार को बहस हुई। अदालती समय पूरा होने के चलते बहस पूरी नहीं हुई। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी। अशोक पाठक के मामले में पक्षकार बनने पर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व अन्य के अधिवक्ताओं की ओर से आपत्ति दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, एएजी शिवमंगल शर्मा व विशेष अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने अदालत को बताया कि उनकी मामले के आरोपियों की ओर से दायर याचिकाओं पर आपत्ति है। राज्य सरकार 26 नवंबर, 2021 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली रिवीजन याचिका को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। इस आदेश में ट्रायल कोर्ट ने पूर्व आईएएस जीएस संधू, ओंकारमल सैनी और निष्काम दिवाकर के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने के संबंध में पेश राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था।

जिलाध्यक्षों को पावर ही नहीं तो संगठन मजबूत कैसे होगा?

- राजस्थान के जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने किया खड़गे और राहुल गांधी से संवाद
- भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष बोले, "राहुल गांधी सड़कों पर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, कांग्रेस नेता घमंड में घूम रहे हैं"

जयपुर। देशभर में पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस आलाकमान देश भर के जिला कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाकर सीधे संवाद कर रहा है और इसी कड़ी में गुरुवार को राजस्थान के जिला कांग्रेस अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया था। जिनसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संवाद किया। इस दौरान राजस्थान के प्रभारी सुखजिंद्र सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे।

संवाद के दौरान प्रमुख रूप से राजस्थान के दो जिला कांग्रेस अध्यक्षों भीलवाड़ा के अक्षय त्रिपाठी और सीकर की सुनीता गठाला को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इस दौरान भीलवाड़ा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी तो पूरे देश में पैदल घूम कर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और हर व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी बात सुनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी और कांग्रेस के नेता घमंड से भरे हुए हैं और आम कार्यकर्ता की तो छोड़े ,संगठन के लोगों को भी तवज्जो नहीं देते हैं। इस दौरान अक्षय त्रिपाठी ने भगवान गणेश और कार्तिकेय की कहानी सुनाते हुए कहा कि जो लोग नेताओं के यहां चक्कर लगाते हैं और चमचागिरी करते हैं, उन्हें सब कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन जो जमीन पर काम करता है, वह हमेशा पीछे धकेल दिया जाता है या लाइन से बाहर किया जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की इन बातों का समर्थन करते हुए कहा कि जल्द ही पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अधिक पावर देकर संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा।

दस दिन में मिले डी.एन.ए. रिपोर्ट : हाईकोर्ट

12 साल से छोटे बच्चों से जुड़े अपराधों का मामला

जयपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में लंबित प्रकरणों पर चिंता जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सभी मिलकर यह प्रयास करें कि जहां तक संभव हो, किसी भी नमूने की रिपोर्ट एक साल से ज्यादा समय से लंबित ना रहे। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि 12 साल से छोटे बच्चों से जुड़े अपराधों में डीएनए रिपोर्ट दस दिन में जारी की जाए। जबकि पॉक्सो से जुड़े अन्य मामलों में रिपोर्ट तीन माह के भीतर दी जाए। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हम दुष्कर्म, अज्ञात शव और हत्या के मामले में भी नमूने जांचने के संबंध में समय सीमा तय करना चाहते हैं। अदालत संसाधनों के उन्नत होने और पदों के भरने से संतुष्ट होने के बाद इस संबंध में आदेश पारित करेगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय करते हुए मामले में की जाने वाली कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास ने अदालत को बताया कि नमूनों की जांच समय पर हो, इसके लिए अधिकारियों की ओर से एक्शन प्लान बनाए एक्शन प्लान का अदालत में पेश किया जाएगा। एएजी ने अदालत को कहा कि सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिकों की अर्जेंट टेपरेरी आधार पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। इन पदों को भरने के बाद 43 और अधिकारी प्रयोगशालाओं को मिल जाएंगे। इसके अलावा दो सहायक निदेशकों की नियुक्ति कर उन्हें कोटा व भरतपुर प्रयोगशाला में नियुक्त किया गया है। एएजी ने अदालत को यह भी बताया कि भरतपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और आगामी अक्टूबर

आई.पी.एस. कलाल के खिलाफ पद के दुरुपयोग को लेकर याचिका

जयपुर। आईपीएस हेमंत कलाल व श्याम नगर एसएचओ सहित अन्य पुलिस कर्मियों की ओर से बैंगलूरु निवासी शैक्षिणक इंस्टीट्यूट संचालक देवेन्द्र कलाल के फोन को अवैध तरीके से ट्रेकिंग कर जबरन अवैध हिरासत में रखने व मारपीट सहित पद के दुरुपयोग का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी। मामले में आईपीएस हेमंत कलाल सहित प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी, एसएचओ श्याम नगर सहित अन्य पुलिसकर्मियों को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज प्रताडना को लेकर 2018 में कलाल की बहन ने उदयपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने भागवत कथा सुनी

जयपुर, 3 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को वैशाली नगर स्थित 'गोविन्द धाम' जानकी पैराडाइज में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बहुत सौभाग्य की बात होती है। श्रीमद् भागवत कथा से भगवान श्रीकृष्ण के साक्षात स्वरुप का ज्ञान होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। शर्मा ने युवा पीढ़ी का आव्हान करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी कथा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात् करे। इस अवसर पर वे भव्य आरती में सम्मिलित हुए। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम दक, विधायक शत्रुघ्न, गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य, अशोक परनामी सहित, संत, साध्वी व बड़ी संख्या में लोगों ने कथा का श्रवण किया।

■ उन्होंने कहा, नवरात्र में श्रीभद् भागवत कथा सुनना सौभाग्य की बात है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वैशाली नगर में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और कथावाचक महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी महाराज से आशीर्वाद लिया।

'चीन के साथ सामान्य स्थिति से पहले हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए'

कांग्रेस नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत के विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे हैं

नयी दिल्ली, 03 अप्रैल। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि चीन भारत के चार हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घुस आया है लेकिन हमारे राजदूत चीन के नेताओं के साथ केक काटते दिख रहे हैं। गांधी ने लोकसभा में शून्य काल में इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया कि चीन द्वारा कब्जाई जमीन को वापस लेने के लिये वह क्या कर रही है?

गांधी ने कहा, मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किये बैठा है और हमारे विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ कुछ समय पहले केक काटते देखे गये। हमारे जवान शहीद हुये थे, उनकी शहादत का जश्न मनाया जा रहा है, केक काटकर। हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति से पहले हमें हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिये।

■ राहुल ने कहा, हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत का जश्न मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि वह विदेश नीति के मामले में न तो बायें झुकेंगी और न ही दायें झुकेंगी, वह भारतीय हैं, वह सीधी खड़ी होंगी। उन्होंने कहा, हम सब इतिहास जानते हैं, जब भाजपा और आरएसएस से ऐसा ही सवाल पूछा जायेगा, तो वे सामने वाले के आगे सिर झुका लेंगे।

राहुल गांधी ने कहा, हमारे सहयोगी (अमेरिका) ने अचानक हमारे ऊपर 26 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। यह हमारे ऑटो और कृषि क्षेत्र पर बहुत बुरा असर डालेगा।

दिल्ली -एनसीआर में पटाखों पर साल भर बैन

नई दिल्ली, 03 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर सालभर का प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है, और केवल 3-4 महीनों के लिए प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने के अधिकार की गारंटी देता है।

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि हर घर में एयर प्यूरीफायर नहीं होता, इसलिए सख्त कदम उठाना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा कि दिल्ली में सभी लोगों के पास एयर प्यूरीफायर नहीं होता, और प्रदूषण से आम जनता की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि दीवाली या अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: प.बंगाल में 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द रहेगी

नयी दिल्ली, 03 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर गुरुवार को मुहर लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया को 'दूषित' और 'सुधार से परे दागदार' घोषित किया।

■ हाईकोर्ट के, पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

■ अदालत ने कहा, पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी तथा इसे सुधारा नहीं जा सकता।

अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी और इसे सुधारा नहीं जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने हालांकि कुछ निर्देशों में संशोधन किया।

शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जो उम्मीदवार पहले कहीं और कार्यरत थे, उन्हें अपने पिछले पदों पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय ने राज्य सरकार से तीन महीने की अवधि के भीतर चयन की नई प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

शीर्ष अदालत का यह फैसला राज्य की ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

खंडवा में कुएं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो गई। सभी 8 शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। शुक्रवार को शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ ही एसडीआरएफ का 15 सदस्यीय दल भी मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू टीम रस्सी और जाली लेकर कुएं में उतरी और शवों को बाहर निकाला।

वनरक्षक भर्ती, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोपी होना पाया गया। वह बाड़मेर के गुढामलानी के रामजी का गोल कस्बा में ग्रेड थर्ड टीचर है।

जांच में नाम सामने आने पर आरोपी टीचर जबराराम फरार हो गया। उसके तमाम ठिकानों पर दबिश देने पर भी आरोपी पकड़ में नही आया।

इसलिए एसओजी ने फरार आरोपी जबराराम जाट पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है।

एक ही झटके में ट्रम्प अमेरिका को 17वीं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहेगी। क्योंकि अमेरिका को निर्यात भारत की जीडीपी का मात्र 2 प्रतिशत है जिसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव सभी देशों पर अलग-अलग होगा। भारत पर 26 प्रतिशत तो चीन पर 54 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार अमेरिकन टैरिफ भारतीय निर्यातों पर प्रभाव चीन की तुलना में आधे से भी कम होगा। कोशिश करके भारतीय निर्यातक अभी भी लागतों को नियंत्रित करने और नवीनतम टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन चीन के लिए यह एक बहुत कठिन कार्य होगा।

दूसरे, चीन अमेरिका को निर्यात पर भारत की तुलना में कहीं अधिक निर्भर है। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि ज्ञात है, घरेलू मांग द्वारा संचालित है, जबकि चीनी अर्थव्यवस्था निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए, चीन के पास अपनी घरेलू आवश्यकताओं से दोगुना स्टील उत्पादन क्षमता है। इसलिए, चीनी स्टील उद्योग के अस्तित्व के लिए उसे निर्यात करना पड़ता है।

कुछ देश और भी अधिक कमजोर हैं, क्योंकि वे कुछ चयनित वस्तुओं के निर्यात पर ही निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पड़ौसी बाँग्लादेश को भी टैरिफ का सामना करना पड़ा है, जो अब तक न्यूनतम या पूरी तरह से छूट प्राप्त थी। बाँग्लादेश की कपड़ों के निर्यात पर निर्भरता को देखते हुए, और विशेष रूप से अमेरिका के साथ, देश की अर्थव्यवस्था 34 प्रतिशत टैरिफ के साथ एक कठिन स्थिति का सामना करेगी।

कुछ विशेषज्ञ अब मानते हैं कि कम से कम तीन क्षेत्रों में भारत के अमेरिका को निर्यात को लाभ हो सकता है। प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का मानना है कि कृषि क्षेत्र में टैरिफ संरचना को देखते हुए भारतीय उत्पादकों को कुछ स्पष्ट लाभ मिलता है और अमेरिका को होने वाले कृषि निर्यात में वृद्धि हो सकती है।

दूसरे, फार्मास्युटिकल निर्यातक उत्साहित महसूस कर रहे हैं। टैरिफ ने दवा उद्योग को प्रभावित नहीं किया है। अमेरिका में भारतीय दवाओं की अच्छी मांग है, और उन्हें वर्तमान टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। सस्ते होने के कारण भारतीय दवा उद्योग यहाँ काफी आगे है।

तीसरे, वस्त्र और दूरसंचार निर्यात के कुछ खंड प्रतिस्पर्धात्मक लाभा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों पर उच्च टैरिफ लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, चीन और वियतनाम पर अब कहीं अधिक टैरिफ लागू किए गए हैं। इसके अलावा, भारत अपने निर्माण क्षेत्र को भी पीएलआई योजनाओं के साथ बढ़ा सकता है, जो प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में कम लागत वाली है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका सभी वस्तुओं का आयात पूरी तरह से बंद कर देगा।

जब दुनिया ट्रम्प के टैरिफ के अनुसार समायोजित हो रही है, तो अनपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। देशों को गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। देश नए अवसर देखेंगे। वैश्विक व्यापार ने निस्संदेह अद्वितीय विकास और प्रगति को जन्म दिया है। इनमें से कई प्रोत्साहक कारक लुप्त हो जाएंगे। इस अनिश्चितता के नए युग में, भारत निस्संदेह सबसे स्थिर और आत्मनिर्भर देशों में से एक होगा। नोमुरा के हालिया निष्कर्षों के अनुसार, भारत वर्तमान व्यापार संघर्ष और आर्थिक समायोजन में एशिया की सबसे लचीली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

बम की धमकी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जन्नत देखना है। कलेक्ट्रेट हमारे साथ नष्ट हो जाएगा। आज का ऑपरेशन पूरा होने के बाद हम शहीद हो जाएंगे। बिलाल-रियाज जो यह पढ़ रहे हैं, आज का दिन है। आप जानते हैं कि क्या करना है। यह हमारा अंतिम कम्युनिकेशन होगा। डीएमके अरिवालयम में नखीरन गोपाल से संपर्क करें। हमने उन्हें एक गुलाबी लिफाफा दिया है, जिसमें डीएमके परिवार की भागीदारी सहित हमारी कहानी का दस्तावेजीकरण करने वाले वीडियो हैं। "अल्लाहु अकबर!" पुलिस टीम ई-मेल करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

'अमेरिका छींकता है, तो विश्व को ज़ुकाम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एस.), इन्फोसिस और विप्रो जैसे उद्योग दिग्गज शामिल हैं, को बढ़े हुए टैरिफ के प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। भारत के निर्यात में प्रमुख योगदान देने वाले इस क्षेत्र की, यू.एस. मार्केट में प्रतिस्पर्धा कमज़ोर पड़ सकती है, जिसका, अनुबंध वार्ताओं और बाज़ार की हिस्सेदारी पर असर पड़ेगा।

फार्मास्युटिकल उद्योग, जिसका अमेरिका को निर्यात लगभग 24 बिलियन डॉलर मूल्य का है, भी संभावित झटकों का सामना कर सकता है। उच्च शुल्क के कारण भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे वे अमेरिकी खरीदारों के लिए कम आकर्षक हो सकते हैं और लाभ के मार्जिन पर असर डाल सकते हैं।

इसी तरह, वस्त्र और परिधान क्षेत्र, जो भारत के निर्यात पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अमेरिकी बाजार में अपनी बढ़त खो सकता है। ऊँचा टैरिफ, मांग और राजस्व को कम कर सकता है, जिससे भारतीय निर्माता अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा, मसाले, चावल, और चाय जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात उच्च कीमतों के कारण कम प्रतिस्पर्धात्मक हो सकते हैं, जिससे भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।

भारत पर लगाए गए तथाकथित "छूट वाले" टैरिफ का श्रेय भारतीय सरकार के सक्रिय प्रयासों को दिया जा सकता है, जिसके तहत सरकार ने अमेरिका के टैरिफ के संभावित परिणामों को संबोधित किया है। भारत ने संभावित व्यापार तनावों को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक संबंधों, बाजार पहुंच बढ़ाने, शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका का दौरा किया। दोनों देशों ने "मिशन 500" पहल के तहत, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

इसके अतिरिक्त, भारत ने अमेरिका की चिंताओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6 प्रतिशत "गूगल कर" को रद्द कर दिया, जिससे सहज वार्ता को सुविधाजनक बनाने की इच्छा के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा, भारत ने अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों, जैसे बादाम, क्रैनबरी और बर्बन व्हिस्की पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत किया जा सके। प्रभाव को कम करने के लिए, भारतीय निर्यातक संभवतः बाजारों में विविधता लाने, उत्पाद मूल्य बढ़ाने, और लागत दक्षता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। नए व्यापार समझौतों और साझेदारियों की संभावना ढूंढने से भी निर्यात मात्रा बनाए रखने और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता को कम करने के वैकल्पिक मार्ग मिल सकते हैं।

हालांकि अमेरिका द्वारा 26 प्रतिशत प्रत्युत्तर शुल्क (रैसिप्रोकल टैरिफ) की घोषणा भारत के निर्यात क्षेत्रों के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती है, लेकिन भारतीय सरकार की सक्रिय सहभागिता और रणनीतिक पहल व्यापारिक मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विकसित होते व्यापार परिदृश्य में निरंतर संवाद और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली रणनीतियों की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को बनाए रखा जाए तथा और अधिक मजबूत किया जा सके।

जयपुर जिंदा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं हो पाई है। इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त किया जाए। गौरतलब है कि जयपुर बम ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी व एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया था। जिंदा बम मामले में एटीएस ने पूर्व एडीजी अरविन्द कुमार जैन व मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन सहित साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया था।

पाकिस्तान से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं बरामद हुई। श्रीकरणपुर थानाधिकारी रामप्रताप वर्मा ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच गजसिंहपुर थाना प्रभारी शीर कौर को सौंपी गई है। बीएसएफ ने जांच के बाद ड्रोन और हेरोइन का पैकेट श्रीकरणपुर पुलिस को सौंप दिया है।

विपक्ष ने राज्यसभा में बड़ी जोशीली बहस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संविधान पर किये गये इस हमले का निशाना आज तो मुस्लिम हैं, लेकिन भविष्य में यह अन्य समुदायों को निशाना बनाने की पूर्व घटना तथा नजीर का काम करेगा। गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का घोर विरोध करती है, क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर ही हमला है तथा अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, का उल्लंघन करता है।

दूसरी तरफ, मोदी सरकार ने विपक्ष के सकारात्मक सुझावों को दरकिनार कर दिया और जेडी (यू) तथा टीडीपी जैसे मित्र दलों पर दबाव डालने की सीमा तक चली गई, लेकिन इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध किया।

यह विधेयक, जो राज्यसभा में सत्तारूढ़ पार्टी तथा उसके मित्र दलों के संख्या बल के चलते पारित हो जायेगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडी (यू), तथा आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी के लिये, मुस्लिमों में अपना समर्थन बनाये रखने के मामले में, एक कड़ी चुनौती बनने जा रहा है। अनुभवी राजनैतिक पर्यवेक्षक, जिनसे इस पत्रकार की बात हुई, एकमत होकर कह रहे हैं कि इन दोनों दलों ने राजनैतिक आत्मघात किया है।

विपक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों को नज़रअंदाज करते हुये, रिजिजू ने कहा, "यह विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है।......... हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों पर निगरानी रखना है, उनका प्रबंधन करना नहीं।"

विपक्षी सदस्यों से समर्थन माँगते हुये, रिजिजू ने कहा कि इस वक्फ विधेयक का उद्देश्य पूर्व सरकारों के अपूर्ण कार्यों को पूरा करना है। उन्होंने कांग्रेस तथा उसके मित्र दलों से वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन की अपील करते हुये कहा कि पूर्ववर्ती कमेटियों द्वारा की गई सिफारिशों को इस नये संशोधित विधेयक में शामिल कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि नये कानून के अनुसार, वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के सभी पंथों के साथ ही पिछड़े वर्गों का भी प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि "हम इसे और अधिक समावेशी बना रहे हैं।" उन्होंने कहा कि "प्रस्तावित सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड के कुल 22 सदस्यों में, चार से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कम से कम दो महिला सदस्य होंगी। स्टेट वक्फ बोर्डों के कुल 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।"

सच्चर कमेटी, जिसने सिफारिश की थी कि सैन्ट्रल वक्फ काउंसिल तथा स्टेट वक्फ बोर्ड को विस्तार देकर, इन्हें समावेशी बनाया जाये, का हवाला देते हुये, उन्होंने सदन को सूचित किया कि कमेटी के आकलन के अनुसार, 2006 में 4.9 लाख सम्पत्तियों से 12000 रूपए की आय थी।

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भूखंड को केवल इस मौखिक आधार पर वक्फ सम्पत्ति होने का दावा करता है कि 500 साल पहले उसके पूर्वजों ने इस वक्फ कर दिया, तो वह इस पर दावा करनेके लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे कुछ साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने कहा, "यूज़र द्वारा वक्फ की सम्पत्ति का दावा मनमर्जी से नहीं हो सकता। इसके अलावा, धारा 40 के तहत, अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है, तो यह स्वतः ही वक्फ प्रोपर्टी घोषित हो जायेगी। हमने इस प्रावधान को हटा दिया है, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी था।"

उन्होंने यह कहते हुये कि वक्फ ने केरल के एक गाँव को अधिगृहीत करने की कोशिश की थी, केरल के सभी सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि केरल में, 600 ईसाई परिवार, जो सभी किसान हैं, अपनी जमीन गँवा चुके हैं। उन्होंने कहा, "हमने इस विधेयक में अपील का अधिकार शामिल किया है। अगर आपको ट्रिब्यूनल से आपका अधिकार नहीं मिलता है, तो आप "अपील के अधिकार" के तहत, अदालत में याचिका पेश कर सकते हैं।"

रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक गरीब मुस्लिमों को ऊपर उठाने वाला, अपील का अधिकार देने वाला तथा यह सुनिश्चित करने वाला है कि परिशिष्ट 5 और 6 के तहत आने वाली जमीन पर वक्फ नियमों के तहत दावा नहीं किया जा सकता।

उन्होंने पुनः जोर देकर कहा कि इन सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद सुलझेंगे तथा जमीन-अधिकार सुरक्षित होंगे। मंत्री ने कहा कि संबंधित जेपीसी ने, अब तक बनाई गई किसी भी अन्य जेपीसी की तुलना में ज्यादा व्यापक काम किया है। उन्होंने कहा, "विभिन्न क्षेत्रों के कुल 284 संगठनों और प्रतिष्ठनों ने अपने विचार एवं सुझाव दिये थे। एक करोड़ से अधिक लोगों ने जेपीसी तथा मंत्रालय में अपनी राय दर्ज कराने के लिये ज्ञापन दिये थे।"

रिजिजू ने कहा कि "सरकार ने यह विधेयक अच्छे उद्देश्यों से पेश किया है तथा इसे "यूएमईईडी" (उमीद) नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस नाम से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये।" सरकार ने इस विधेयक को नया नाम "यूनिफाइड वक्फ एम्पावरमैंट, एफिसिएन्सी एंड डवलपमैंड (यूएमईईडी) बिल" दिया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908